नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 064
दि. 06.12.2025,
शनिवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : JIGNESHKUMAR PETHABHAI VAGHELA Regd. Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Centre, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad-382 424, Gujarat, India.

Phone : 76983 33307 (M) 84859 51747, 70963 33307 ● Email : navsarjansanskruti2016@gmail.com ● Email : navsarjansanskruti2016@yahoo.com ● Website : www.navsarjansanskruti.com

हेल्थ से नेशनल सिक्योरिटी तक: पान मसाला–सिगरेट पर नया सेस पास, अब देश की सुरक्षा में खर्च होगा टैक्स का पैसा

नई दिल्ली की लोकसभा में शुक्रवार का दिन उस नए बदलाव का साक्षी बना, जिसने पहली बार स्वास्थ्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा को एक ही धागे में पिरो दिया। हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल पास होने के साथ ही देश में बिकने वाले पान मसाला, सिगरेट और अन्य हानिकारक उत्पादों पर एक नया उपकर लगाया जाएगा, जिसका पूरा फंड सेना की तैयारियों, आधुनिक युद्ध उपकरणों और बड़े पैमाने पर चलने वाली स्वास्थ्य योजनाओं में खर्च किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिल पेश करते हुए कहा कि कारगिल युद्ध के समय देश की सेना 70–80% हथियारों और उपकरणों की कमी से जूझ रही थी। बजट की कमी ने उस समय की तैयारियों को गंभीर रूप से प्रभावित किया और सरकार इस बात को लेकर आश्वस्त रहना चाहती है कि भविष्य में जब भी देश कठिन समय से गुजरे, संसाधनों की बाधा सेना के कदम न रोक पाए।

वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि उपकर केवल उन वस्तुओं पर लगाया जाएगा जो सीधे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती हैं, ताकि जनता पर अतिरिक्त वित्तीय भार न आए और फिर भी देश को जरूरी संसाधन मिल सकें। पान मसाला और सिगरेट जैसी वस्तुएँ पहले ही ऊंचे टैक्स दायरे में हैं, और अब 40% जीएसटी के ऊपर एक अतिरिक्त स्वास्थ्य–राष्ट्रीय सुरक्षा सेस लगाया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे दो बड़े लक्ष्य पूरे होंगे—एक, जनस्वास्थ्य की सुरक्षा और दूसरा, आधुनिक युद्ध की आवश्यकताओं के लिए एक स्थिर और सुनिश्चित फंडिंग व्यवस्था।

लेकिन लोकसभा में यह फैसला इतना सुगम नहीं रहा। विपक्षी सांसद हनुमान

बेनीवाल ने पान मसाला महंगा करने की सरकारी नीति पर सवाल उठाया और कहा कि जब बड़े-बड़े सेलेब्रिटी इन उत्पादों का विज्ञापन कर रहे हैं, तब सरकार उन विज्ञापनों को रोकने के लिए क्या कर रही है। कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल ने इसे जटिल बिल बताते हुए कहा कि इसके कुछ क्लॉज मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों जैसे दिखाई देते हैं। बहस के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दो टूक रहीं—उन्होंने कहा कि मॉर्डन वॉरफेयर टेक्नोलॉजी, ड्रोन सिस्टम, साइबर डिफेंस, और मल्टी-डोमेन ऑपरेशंस आज की युद्ध रणनीति का अहम हिस्सा हैं। ऑपरेशन सिंदूर और मिशन सुदर्शन चक्र के उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि भविष्य की लड़ाइयाँ सिर्फ़ साहस से नहीं बल्कि अत्याधुनिक तकनीक से जीती जाएँगी और यह तकनीक तभी संभव है जब फंडिंग मजबूत हो।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार उन वस्तुओं को महंगा कर रही है जो स्वयं देश को स्वास्थ्य के मोर्चे पर कमजोर बनाती हैं। इनकम टैक्स में की गई छूट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि आम नागरिक पर बोझ न पड़े यह सरकार की प्राथमिकता है, और यही वजह है कि सेस केवल डिमेरिट गुड्स पर ही लगाया जा रहा है। कुछ सदस्यों द्वारा यह सवाल उठाने पर कि रक्षा बजट पान मसाले के टैक्स पर क्यों निर्भर होना चाहिए, वित्त मंत्री ने कहा कि किसी वित्त मंत्री का पहला दायित्व संसाधन जुटाना होता है—और यह उपकर उसी दिशा का कदम है। यह बिल कानून बनते ही देश के स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों पर प्रत्यक्ष असर डालेगा। भारत पहले ही तंबाकू से जुड़े खतरों का सबसे बड़ा भुगतमान है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, हर साल भारत में 10 लाख से ज्यादा लोग सिगरेट के कारण समय से पहले मौत का शिकार हो जाते हैं। यदि अन्य तंबाकू उत्पादों से होने वाली मौतें जोड़ दें तो यह आंकड़ा बढ़कर लगभग 13.5 लाख हो जाता है। तंबाकू से होने वाली मौतें सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि उन परिवारों की कहानियाँ हैं जो हर दिन अपने किसी सदस्य को खो देते हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज, लंदन की एक स्टडी के अनुसार, हर सिगरेट जीवन के लगभग 20 मिनट कम कर देती है। दस साल तक रोज 10 सिगरेट पीने वाला व्यक्ति अपनी जिंदगी के 500 दिन धुएं में उड़ा देता है। भारत में आज 25.3 करोड़ लोग तंबाकू का सेवन करते हैं—20 करोड़ पुरुष और 5.3 करोड़ महिलाएँ। दुनिया में चीन के बाद तंबाकू सेवन में भारत दूसरे स्थान पर है। ऐसे में यह उपकर सिर्फ सुरक्षा के लिए फंड जुटाने का तरीका नहीं, बल्कि एक अप्रत्यक्ष स्वास्थ्य सुधार नीति भी है जो इन उत्पादों को महंगा बनाकर उनकी खपत को घटाएगी। लोकसभा में हुई लंबी बहस और मंत्रियों की स्पष्टता के बावजूद देशभर में अब चर्चा इस बात पर है कि क्या यह कदम तंबाकू की लत पर लगाम लगाएगा, क्या यह स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के लिए एक स्थायी समाधान बनेगा, और क्या इस उपकर से सेना की आधुनिक जरूरतें पूरी होंगी। फिलहाल इतना तय है कि संसद ने एक ऐसा कानून पास किया है जिसमें पहली बार किसी टैक्स को सीधे देश की सुरक्षा से जोड़ा गया है—और आने वाले वर्षों में इसका असर टेबल के दोनों सिरों पर देखने को मिलेगा: एक तरफ सैनिकों की ढाल मजबूत होगी, दूसरी तरफ जनता के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाली वस्तुएँ धीरे-धीरे महंगी होकर पीछे हटेंगी।

18 गुना बढ़ा यूपी का रेल बजट: रेलमंत्री का दावा, मोदी सरकार ने प्रदेश में रेलवे विकास की रफ्तार बदल दी

नई दिल्ली। राज्यसभा में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में रेलवे के अभूतपूर्व विकास पर चर्चा के दौरान केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि नरेन्द्र मोदी सरकार ने प्रदेश की रेल परियोजनाओं के लिए बजट में ऐतिहासिक वृद्धि की है। रेल मंत्री के अनुसार 2014 से पहले जहां उत्तर प्रदेश को मात्र 1,100 करोड़ रुपये का रेल बजट मिलता था, वही बजट अब बढ़कर 18 गुना होकर 19,800 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। उनके अनुसार यह केवल संख्याओं का विस्तार नहीं, बल्कि केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश के समग्र बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दृढ़ इच्छा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश भौगोलिक और जनसंख्या दोनों दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है, और इसलिए यहां कनेक्टिविटी बढ़ाना राष्ट्रीय विकास के लिए आवश्यक है।

मंत्री ने बताया कि बढ़े हुए बजट आवंटन का लाभ प्रदेश के हर क्षेत्र को मिलना शुरू हो गया है। नई रेलवे लाइनें बिछाने, ट्रैक दोहरीकरण, विद्युतीकरण, आधुनिक सिग्नलिंग सिस्टम, स्टेशन पुनर्विकास और यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने

जैसे कई प्रोजेक्ट पहले की तुलना में कहीं तेज़ गति से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे का ढांचा मजबूत होने से न केवल उत्तर प्रदेश के शहर आपस में और अधिक सुगमता से जुड़ पाएंगे, बल्कि माल परिवहन भी सरल और तेज़ होगा, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था पर प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

प्रश्नकाल के दौरान बलिया और बक्सर की परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए रेल मंत्री ने बताया कि बलिया जिले से फिलहाल 82 ट्रेन सेवाएं चलाई जा रही हैं, जो पिछले वर्षों की तुलना में एक बड़ा विस्तार है। बलिया रेलवे स्टेशन को सांस्कृतिक थीम पर पुनर्विकसित किया जा रहा है, जिसमें भोजपुरी संस्कृति और स्थानीय धरोहर को विशेष रूप से दर्शाया जाएगा। इसी तरह, बक्सर में भी स्टेशन को पौराणिक स्वरूप दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रामायण सर्किट पर यात्रा करने वाले यात्रियों और तीर्थयात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्थानीय आध्यात्मिक और ऐतिहासिक पहचान को स्टेशन के डिजाइन में विशेष रूप से शामिल किया जा रहा है।

कुशीनगर से जुड़े सवाल पर रेल मंत्री ने बताया कि यह बौद्ध पर्यटन के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है और यहां कनेक्टिविटी बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लखीमपुर खीरी और पूर्वांचल के अन्य जिलों से संबंधित मुद्दों पर भी उन्होंने आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया। रेल मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के साथ-साथ बिहार के लिए भी अनेक परियोजनाएं तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और रेलवे की भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अत्याधुनिक उपकरणों, सुरक्षा तंत्र और लॉजिस्टिक कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं।

अमृत भारत स्टेशन योजना पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि देश के सैकड़ों स्टेशनों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। इसमें वेटिंग लाउंज, लिफ्ट-एस्केलेटर, फूड कोर्ट, बेहतर प्रकाश व्यवस्था, डिजिटल डिस्प्ले, पॉडियम-स्टाइल भवन संरचना और हर यात्री के लिए सुगम पहुंच जैसी सुविधाएं शामिल हैं। मंत्री ने दावा किया कि नई तकनीक, हाई-स्पीड रेल, सेमी-हाई-स्पीड कॉरिडोर और फ्रेट नेटवर्क को विस्तार देने के साथ भारतीय रेलवे अपनी सबसे तेज़ संक्रमण प्रक्रिया से गुजर रहा है।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के दशक भर के शासन में उत्तर प्रदेश के रेल निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में जितनी वृद्धि दर्ज की गई है, उतनी वृद्धि इससे पहले कभी नहीं देखी गई। रेल मंत्री ने विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में पूरी तरह आधुनिक सुविधाओं से लैस रेलवे न केवल यात्रियों के अनुभव को बदल देगा, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी नई गति देगा।

इंडिगो संकट के बीच बड़ा फैसला: DGCA ने बदले नियम, पायलटों को अब मिलेगा अनिवार्य साप्ताहिक विश्राम

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो में जारी परिचालन संकट के बीच नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पायलटों की उड़ान ड्यूटी समय सीमा (एफडीटीएल) के नियमों में संशोधन कर दिया है। नए निर्देशों के तहत अब पायलटों को साप्ताहिक छुट्टी देने के बजाय अनिवार्य साप्ताहिक विश्राम अवधि प्रदान की जाएगी, जिससे उनकी थकान कम हो और उड़ान संचालन में सुरक्षा बढ़ाई जा सके। डीजीसीए का यह फैसला ऐसे वक्त पर आया है जब इंडिगो सहित कई एयरलाइनों में क्रू की कमी, रोस्टर के दबाव और नए नियमों की कठोरताओं के कारण उड़ानों में लगातार देरी और रद्दीकरण बढ़ रहे थे, जिससे हजारों यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ी। डीजीसीए ने स्पष्ट किया कि हालिया संकट की पृष्ठभूमि में नई एफडीटीएल गाइडलाइंस की सख्ती एक बड़ा कारण रही है, जिसने एयरलाइनों, विशेषकर इंडिगो, पर जबरदस्त दबाव डाला। नियमों के अनुसार पायलटों की साप्ताहिक छुट्टी 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे की गई थी, रात की परिभाषा को 00:00 से 05:00 के बजाय 00:00 से 06:00 तक बढ़ाया

गया, एक सप्ताह में रात की लैंडिंग की सीमा 6 से घटाकर केवल 2 की गई और लगातार दो से अधिक रात ड्यूटी पर रोक लगा दी गई। एयरलाइनों का तर्क था कि सुरक्षा के अनुरूप ये मानक तो आवश्यक हैं, लेकिन इन्हें अचानक लागू किए जाने के चलते रोस्टर तैयार करना अत्यंत कठिन हो गया। परिणामस्वरूप उड़ानों की समय-सारिणी बिगड़ने लगी और हवाई यातायात में अप्रत्याशित अव्यवस्था पैदा हो गई।

एयरलाइन कंपनियों ने डीजीसीए को दिए गए अपने अभ्यावेदन में आग्रह किया था कि नियमों में थोड़ी ढील या चरणबद्ध व्यवस्था आवश्यक है, ताकि मौजूदा व्यवधानों का समाधान किया जा सके। पायलटों और क्रू की उपलब्धता कम होने लगी थी, जिससे उड़ानों की वैधता अवधि में बढ़ोतरी, गेट पर लंबा इंतजार और यात्रियों की शिकायतें लगातार बढ़ती जा रही थीं। इस स्थिति को देखते हुए नागर विमानन मंत्रालय ने भी डीजीसीए को संचालन सुधारने और यात्रियों को राहत देने के लिए व्यावहारिक समाधान खोजने की सलाह दी।

इसी बीच इंडिगो ने गुरुवार देर रात नागर विमानन मंत्री और डीजीसीए अधिकारियों के साथ हुई एक अहम बैठक में आश्वासन दिया कि 10 फरवरी तक उसकी सेवाएं पूरी तरह सामान्य हो जाएंगी। कंपनी ने बताया कि वह रोस्टरिंग व्यवस्था में सुधार, विमान के टर्नअराउंड समय को कम करने, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ बेहतर समन्वय और यात्रियों के प्रबंधन में दक्षता लाने पर तेजी से काम कर रही है। कंपनी का कहना है कि नए दिशा-निर्देश उसके परिचालन को संतुलित करने में मदद करेंगे और पायलटों पर बढ़ते तनाव को भी कम किया जा सकेगा। संशोधित गाइडलाइंस जारी करते हुए डीजीसीए ने पायलटों से भी सहयोग की अपील की है। नियामक का मानना है कि पर्याप्त विश्राम उड़ान सुरक्षा की रीढ़ है और इसे किसी भी स्थिति में कमजोर नहीं किया जा सकता। साथ ही एयरलाइनों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने परिचालन को इस तरह संतुलित करें कि न केवल पायलटों को आवश्यक विश्राम मिले, बल्कि यात्रियों को भी न्यूनतम असुविधा हो। डीजीसीए का विश्वास है कि बदले हुए नियम और एयरलाइनों तथा पायलटों के बीच सामंजस्य आने वाले दिनों में उड़ान संचालन को स्थिरता प्रदान करेंगे। देश के उड्डयन क्षेत्र में यह बदलाव उस समय आया है जब बढ़ती मांग, सीमित पायलटों की संख्या और जटिल परिचालन स्थितियाँ पूरे उद्योग के सामने चुनौती बनकर खड़ी हैं। ऐसे में डीजीसीए की यह पहल सुरक्षा, दक्षता और यात्री सुविधा—तीनों मोर्चों पर सुधार लाने की दिशा में निर्णायक कदम मानी जा रही है।

भारत में हवाई किरायों का ऐसा उछाल कि आसमान भी शर्माए—6 हजार वाला टिकट 50 हजार पर, घरेलू उड़ानें लंदन–पेरिस से महंगी

नई दिल्ली। भारत का विमानन क्षेत्र इन दिनों एक ऐसे भंवर में फंस गया है, जिसकी मार सीधे आम यात्रियों पर पड़ रही है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो में गहरे स्तर पर चल रहे परिचालन संकट का असर अब पूरे बाजार पर साफ दिख रहा है। हालात ऐसे हैं कि सामान्य दिनों में 6 से 10 हजार रुपये में मिलने वाला घरेलू उड़ान टिकट अचानक 50 से 60 हजार रुपये तक पहुंच गया है। कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, पटना और उदयपुर जैसे प्रमुख मार्गों पर किराया इतना बढ़ चुका है कि अब लंदन और पेरिस की अंतरराष्ट्रीय उड़ानें तुलनात्मक रूप से सस्ती लगने लगी हैं।

यात्रियों के लिए यह स्थिति मानो झटका बनकर सामने आई है। हवाई अड्डों पर लंबी कतारें, रद्द उड़ानों की लगातार घोषणाएं और टिकट काउंटरों पर मौजूदगी दर्ज करने को मजबूर हजारों यात्री—यह सब मिलकर संकट की एक तस्वीर खींचते हैं, जिसमें न कोई स्पष्ट अंत दिखाई देता है और न ही कोई तुरंत राहत का संकेत।

सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि घरेलू किराया रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया? विशेषज्ञों का कहना है कि यह संकट केवल उड़ान रद्द होने तक सीमित नहीं है। इंडिगो द्वारा एक झटके में सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दिए जाने से हजारों सीटें बाजार से गायब हो गईं। ऐसी स्थिति में अन्य एयरलाइंस—विस्तारा, एयर इंडिया, स्पाइसजेट—की सीमित सीटों पर अचानक लाखों यात्रियों का दबाव पड़ा। जैसे ही मांग बढ़ी, एयरलाइंस का डायनामिक प्राइसिंग सिस्टम सक्रिय हो गया और टिकटों के दाम मिनटों में आसमान पर जा चढ़े।

उधर, देश में शादी-ब्याह और त्योहारों का सीजन भी चल रहा है, जब सामान्य समय की तुलना में यात्रा की मांग लगभग दोगुनी होती है। इस वजह से किराए का उछाल और तेज हो गया। बाजार के हिसाब से यह एक आदर्श तूफान जैसा है—मांग ज़रूरत से कहीं अधिक और आपूर्ति बेहद कम।

इंडिगो का कहना है कि नए एफडीटीएल नियम, पायलटों की कमी और रोस्टरिंग में आई समस्याओं ने स्थिति को बिगाड़ा है। एयरलाइंस के अनुसार, क्रू को अतिरिक्त विश्राम देने के कारण उड़ानों की संख्या अचानक कम हो गई। डीजीसीए ने अब इन नियमों में ढील दी है, लेकिन एयरलाइन के परिचालन को फिर से सामान्य स्तर पर लाने में समय लगेगा।

इस संकट के व्यापक प्रभाव केवल यात्रियों की जेब तक सीमित नहीं हैं। विमानन विशेषज्ञों का मानना है कि बाजार संतुलन इस समय गंभीर रूप से प्रभावित है। अगर तेजी से सुधार नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में किरायों का ग्राफ और ऊपर जा सकता है, जिससे हवाई यात्रा आम लोगों के लिए विलासिता बनकर रह जाएगी। उम्मीद सिर्फ यही है कि एयरलाइंस और नियामक संस्थाएं मिलकर जल्द समाधान निकालें, अन्यथा भारत की घरेलू उड़ानों का यह महँगा सफ़र अभी कुछ समय तक जारी रहने वाला है।

‘मदर मैरी कम्स टू मी’ पर रोक की मांग अस्वीकार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा—यह याचिका सिर्फ पब्लिसिटी का प्रयास

नई दिल्ली। साहित्य, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और न्यायिक प्रक्रिया—इन तीनों के संगम पर खड़ी एक याचिका को उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को निर्णायक टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया। अरुंधति राय की नई पुस्तक ‘मदर मैरी कम्स टू मी’ की बिक्री और प्रचार पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि यह मामला गंभीर कानूनी मुद्दा नहीं, बल्कि पब्लिसिटी का प्रयास अधिक प्रतीत होता है।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने दो टूक शब्दों में कहा कि याचिका में ऐसा कोई आधार नहीं है, जिसके आधार पर न्यायालय इस पुस्तक के प्रकाशन या बिक्री पर रोक लगाने जैसा कठोर कदम उठाए। अदालत ने खुलकर टिप्पणी की कि “हम इस तरह की याचिकाओं को प्रोत्साहित नहीं कर सकते, जो सिर्फ चर्चा बटोरने के लिए दायर की जाती हैं।”

यह मामला उसी समय उठ खड़ा हुआ था जब केरल उच्च न्यायालय ने 13 अक्टूबर को इसी प्रकार की याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद याचिकाकर्ता राजसिम्हम ने उच्चतम न्यायालय में अपील की, आरोप लगाते हुए कि पुस्तक के कवर पेज पर अरुंधति राय को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है और यह सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA) का उल्लंघन है। उनके अनुसार, ऐसे चित्रण से तंबाकू सेवन को प्रोत्साहन मिलता है, इसलिए पुस्तक की बिक्री और प्रचार दोनों पर रोक लगनी चाहिए।

लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को नकार दिया। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि पुस्तक के कवर पर चेतावनी दी गई है, और राय एक स्थापित, सम्मानित लेखिका हैं जिनके लेखन को महज़ एक तस्वीर के आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि कला, साहित्य और रचनात्मक अभिव्यक्ति को सीमित करने के लिए बेहद ठोस आधार चाहिए—सिर्फ व्यक्तिगत असहमति या एक प्रतीक को देखकर असुविधा महसूस होना पर्याप्त कारण नहीं हो सकता।

दरअसल, अदालत का निर्णय इस बात का भी स्मरण कराता है कि लोकतंत्र में किताबें प्रश्न उठाने, विचारों को चुनौती देने और समाज के भीतर संवाद उत्पन्न करने का माध्यम होती हैं। उनका मूल्यांकन कानून के दायरे में निश्चित तौर पर होना चाहिए, लेकिन केवल भावनात्मक अपील के आधार पर नहीं।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका खारिज किए जाने के साथ अब ‘मदर मैरी कम्स टू मी’ की बिक्री और प्रचार पर किसी भी प्रकार की कानूनी रोक का रास्ता बंद हो गया है। यह फैसला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक दायरे को फिर एक बार मजबूती से रेखांकित करता है और याद दिलाता है कि साहित्य पर प्रतिबंध लगाने की मांगों के प्रति अदालतें बेहद सतर्क और विवेकपूर्ण रुख अपनाती हैं।

संपादकीय

सिमटते जलस्रेत व ज़हरीला होता पेयजल

निस्संदेह, पंजाब इन दिनों दोहरे जल संकट से जूझ रहा है। एक ओर जहां अंधाधुंध भू-गर्भीय जल के दोहन से उसका जलस्तर गिर रहा है, वहीं कीटनाशकों व रासायनिक खादों के बेतहाशा इस्तेमाल से पानी जहरीला होता जा रहा है। हाल ही में केंद्रीय भूजल बोर्ड यानी सीजीडब्ल्यूबी के नवीनतम आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं। संस्था के नवीनतम निष्कर्ष बताते हैं कि पंजाब 156.36 फीसदी भूजल दोहन के साथ इसके अत्यधिक इस्तेमाल में देशभर में अग्रणी है। जो इस बात को रेखांकित करता है कि पंजाब में इसके जलस्रोतों का कितने खतरनाक ढंग से अत्यधिक दोहन किया जा चुका है। लेकिन यह संकट यहीं समाप्त नहीं हो जाता। इस संकट से जुड़ी त्रासदी यह भी है कि सीजीडब्ल्यूबी की नवीनतम वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट-2025 बताती है कि पंजाब में परीक्षण किए गए भूजल के 62.5 फीसदी नमूनों में यूरेनियम सुरक्षित सीमा से कहीं अधिक मात्रा में पाया गया है। निश्चित रूप से भू-गर्भीय जल के अत्यधिक दोहन और पानी की गुणवत्ता में गिरावट में गहरा संबंध है। दरअसल, अत्यधिक भूजल दोहन से पानी का स्तर नीचे चला जाता है, जिसके चलते गहरे बोरवेल लगाने पड़ते हैं। जो भूगर्भीय रूप से अस्थिर, खनिज-समृद्ध परतों से पानी खींचते हैं। जो अक्सर यूरेनियम, आर्सेनिक, नाइट्रेट या लवणता से भरी होती हैं। इसके साथ ही, दशकों से चली आ रही सघन कृषि, अधिक सिंचाई वाली फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिये भारी मात्रा में सिंचाई और रासायनिक उर्वरकों की जरूरत होती है। जिसके चलते भूजल व मिट्टी दोनों ही में प्रदूषकों का रिसाव तेज हो जाता है। इस भयावह संकट को पिछले दिनों राज्यसभा में राजनीतिक आवाज तब मिली, जब सांसद राघव चड्ढा ने पंजाब में विषाक्त जल संकट पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने चेताया था कि भारी धातुओं और रेडियोधर्मी प्रदूषकों वाला पानी आम लोगों के स्वास्थ्य पर घातक असर डाल रहा है। ऐसा करके उन्होंने देश के नीति नियंताओं को आईना दिखाने का प्रयास ही किया है।

दरअसल, आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा में इस चिंता को अभिव्यक्त करके, पर्यावरणीय आंकड़ों के जरिये लंबे समय से दिए जा रहे संकेतों को स्पष्ट रूप से उजागर ही किया है। हमें इस बात का अहसास होना चाहिए कि यह अब कोई दूरगामी पर्यावरणीय चिंता नहीं बल्कि हमारे सामने एक उभरती हुई जन-स्वास्थ्य की आपात स्थिति ही है। देश में अकसर उस ट्रेन का जिक्र किया जाता रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में पंजाब के लोग कैंसर के उपचार के लिये राजस्थान के विभिन्न अस्पतालों में जाया करते हैं। जिसे अकसर कैंसर ट्रेन के नाम से पुकारा भी जाता रहा है। निस्संदेह, राज्य के कुओं, बोरवेल या हैंडपंप पर निर्भर लाखों पंजाबियों के लिये, इसका मतलब है कि उनके लिये रोजाना पीने का पानी ही स्वास्थ्य खतरा बन सकता है। जिसके उपयोग से उनके गुर्दे की क्षति, कैंसरकारी घातक प्रभाव और प्रजनन व शारीरिक विकास संबंधी नुकसान हो सकता है। निस्संदेह, इस दिशा में तत्काल निर्णायक कार्रवाई करने की सख्त आवश्यकता है। समय की मांग है कि तत्काल प्रभाव से भूजल के अंधाधुंध दोहन पर सख्त अंकुश लगाया जाए। इसके लिये बेहद जरूरी है कि कृषि क्षेत्र पर ध्यान देकर, कम पानी का उपयोग करने वाली फसलों को प्राथमिकता के आधार पर प्रोत्साहित किया जाए। राज्य के हर शहर व गांव में भूजल गुणवत्ता परीक्षण की सुविधा सहज रूप से उपलब्ध करायी जाए। प्रदूषित पेयजल के प्रभावी उपचार के साथ ही सुरक्षित जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही औद्योगिक व कृषि प्रदूषकों पर नियंत्रण के लिये पारदर्शी व सख्त कानून व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि स्वच्छ पेयजल अनंत मात्रा में उपलब्ध नहीं है। हम इसे असीमित संसाधन के बजाय एक नाजुक जीवन रेखा के रूप में देखें। यदि आज हमने समय रहते हुए पेयजल को सुरक्षित व संरक्षित नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियां पेयजल संकट से जूझने को अभिशप्त होंगी। इतना ही नहीं, उन्हें सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट भी विरासत के रूप में मिलेगा। जिसके लिये वे हमें कभी माफ नहीं करेंगी।

भरोसा जीतकर हो सुरक्षा उपायों पर अमल

> “ऐसा नहीं है कि सरकारी एप पर जनता का भरोसा नहीं होता। कोविड के दौरान ‘आरोग्य सेतु’ का देश की जनता ने भरपूर इस्तेमाल किया। वह डिजिटल स्वास्थ्य एप था, जो अब आरोग्य सेतु 2.0 के रूप में और बेहतर हो चुका है।

दूरसंचार विभाग ने स्मार्टफोन कंपनियों को ‘संचार साथी’ एप्लीकेशन को अनिवार्य रूप से प्री-लोड करने के अपना आदेश वापस लेकर अच्छा काम किया है। इसे लागू करने का बेहतर तरीका यही था कि लोगों पर छोड़ दिया जाता कि वे चाहें, तो इसे डाउनलोड कर लें और न चाहें तो न करें। इसके फायदों को देखते हुए वह खुद ही लोकप्रिय हो जाएगा। हां, फायदों की जानकारी लोगों को जरूर दी जानी चाहिए थी। इसे लेकर गोपनीयता और संभावित निगरानी को लेकर चिंताएं पैदा हुईं, जिनके पीछे भले ही कोई आधार नहीं रहा होगा, पर वे वाजिब थीं। संचार मंत्रालय ने अब बुधवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, ‘सरकार ने मोबाइल निर्माताओं के लिए प्री-इंस्टॉलेशन को अनिवार्य नहीं बनाने का निर्णय लिया है।’

मतलब यह भी नहीं है कि सरकार साइबर अपराधों को रोकने की अपनी जिम्मेदारी से हाथ धो ले। वस्तुतः यह साख का सवाल है। पिछले सोमवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने देशभर से सामने आए डिजिटल अरेस्ट के मामलों की देशभर में जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा, डिजिटल अरेस्ट तेजी से बढ़ता साइबर क्राइम है। इसमें ठग खुद को पुलिस, कोर्ट या सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताकर वीडियो/ऑडियो कॉल के जरिए पीड़ितों, खासकर सीनियर सिटिजन को धमकाते हैं और उनसे पैसे वसूलते हैं।

वस्तुतः यह मामला जागरूकता के अभाव की ओर इशारा करता है, साथ ही जनता और सरकार के बीच की दूरी को भी बताता है। कोई व्यक्ति खुद को पुलिस वाला बताकर जब फोन करता है तो सामने वाला डरता है। उसे लगता है कि किसी गलत मामले में उसे फंसाया जा सकता है। लोगों के मन में यह डर बहुत गहरा बैठा हुआ है। ठगों ने उसका ही दोहन किया है, अन्यथा जब आपने कोई गलती की नहीं है, तो डरने की जरूरत ही क्या है? इसके शिकार

साधारण लोग ही नहीं, पढ़े-लिखे लोग भी हुए हैं।

ऐसे अपराधों को लेकर मीडिया में जितनी खबरें आई हैं, उतनी अपराधियों पर कार्रवाई की खबरें नहीं आई हैं। पिछले कई साल से यह काम चल रहा है। बड़े स्तर पर संगठित गिरोह इसका संचालन कर रहे हैं। इसका संगठित कारोबार अंतरराष्ट्रीय शक्ल ले चुका है। इसमें धोखाधड़ी वाले कॉल के माध्यम से लोगों को डराकर उनसे पैसे ऐंठे जाते हैं। अपराधी सरकारी अधिकारियों का रूप धारण करते हैं और पीड़ितों को झूठे कानूनी आरोपों में फंसाने की धमकी देते हैं। इन घोटालों के साथ संगठित अपराध सिंडिकेट जुड़े हैं। इनमें वित्तीय संस्थानों का दुरुपयोग किया जाता है, जिससे पैसे को क्रिप्टोकरेंसी में बदलकर उसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है।

ऐसा नहीं है कि सरकारी एप पर जनता का भरोसा नहीं होता। कोविड के दौरान ‘आरोग्य सेतु’ का देश की जनता ने भरपूर इस्तेमाल किया। वह डिजिटल स्वास्थ्य एप था, जो अब आरोग्य सेतु 2.0 के रूप में और बेहतर हो चुका है। वह व्यापक वन हेल्थ एप है, जिसे स्वास्थ्य, कल्याण, चिकित्सा रिकॉर्ड, बीमा और परिवार की देखभाल सभी को एक ही स्थान पर प्रबंधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसी तरह डिजिटल लॉकर जैसे उपयोगी ऐप भी हैं।

बहरहाल, दूरसंचार विभाग ने 28 नवंबर को जारी प्रारंभिक आदेश में स्मार्टफोन निर्माताओं और आयातकों को नए फोन और पुराने फोनों में भी सॉफ्टवेयर अपडेट के माध्यम से संचार साथी एप्लिकेशन पहले से इंस्टॉल करने का निर्देश दिया था। इसमें कहा गया था कि एप के कार्यों को अक्षम या प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। इसे साइबर सुरक्षा एप्लिकेशन बताया गया, जो उपयोगकर्ताओं को धोखाधड़ी वाले कॉल, संदेशों और चोरी हुए मोबाइल फोन की रिपोर्ट करने की सुविधा देता है। बेशक इन सुविधाओं की नागरिकों को जरूरत है, पर उन्हें लगता है कि इनकी आड़ में सरकार गुपचुप उनकी निगरानी करने जा रही है। शायद अपने विरोधियों को प्रताड़ित करने का तरीका उसने खोजा है।

आदेश वापस लेने के पहले दिन में, दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सरकार ज़रूरत पड़ने पर आदेश में बदलाव के लिए तैयार है। सिंधिया ने संसद में कहा, ‘...अगर हमें प्राप्त फीडबैक के आधार पर आदेश में बदलाव करना पड़ा, तो हम इसके लिए तैयार हैं।’ निगरानी संबंधी चिंताओं पर उन्होंने कहा, ‘न तो जासूसी संभव है और न ही की जाएगी।’ एक दिन पहले सिंधिया ने स्पष्ट किया था कि एप वैकल्पिक है और उपयोगकर्ता इसे हटा सकते हैं। उन्होंने कहा, ‘प्रत्येक नागरिक की डिजिटल सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।’ स्मार्टफोन निर्माताओं एपल और गूगल को, जिनके पास क्रमशः दो सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम आईओएस और एंड्रॉइड हैं, इस आदेश को लेकर भी आपत्तियाथीं। इन कंपनियों का दृष्टिकोण है कि दुनिया में कहीं भी अपने उपकरणों में सरकारी एप्स प्री-लोड करने का इन फ़ोन निर्माताओं का कोई इतिहास या मिसाल नहीं है। इसे लागू करने से परिचालन संबंधी चुनौतियां अलग से पैदा होंगी, क्योंकि इसके लिए उन्हें आईओएस और एंड्रॉयड में विशेष रूप से भारत के अनुरूप बदलाव करने पड़ सकते हैं।

सिविल सोसायटी के कार्यकर्ताओं ने एप को अनिवार्य बनाने से लोगों की निजता पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों को लेकर चिंता जताई थी, क्योंकि इसे प्री-लोड करने से पसंद और सहमति के सिद्धांत विफल हो जाते हैं, और भविष्य में ‘कार्यात्मक विस्तार’ की संभावना बनी रहती है। ‘कार्यात्मक विस्तार’ का अर्थ है किसी सिस्टम का उसके मूल उद्देश्य से परे हटकर धीरे-धीरे विस्तार।

साइबर अपराधों की बढ़ती जटिलता, ‘डिजिटल गिरफ्तारियों’ से लेकर गुमनाम, बड़े पैमाने पर सीमा पार घोटालों तक, उनसे निपटना जरूरी और मुश्किल दोनों बना दिया है। साइबर अपराधियों ने एक सुरक्षा अंतराल का फायदा उठाया है, जिसमें इंस्टेंट मैसेजिंग एप्स पर उपयोगकर्ता के सिम कार्ड हटा दिए जाने के बाद भी सक्रिय रहते हैं, और इस गुमनामी का उपयोग वे धोखाधड़ी करने के लिए करते हैं। नकली या छेड़छाड़ किए गए आईएमईआई नंबरों के बड़े पैमाने पर उपयोग ने भी अपराधियों को ट्रैक करना कानून प्रवर्तन के लिए लगभग असंभव बना दिया है। इसलिए यह जरूरी भी हो गया है कि सरकार इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कमजोरियों को दूर करने के लिए बेहतर उपकरणों की तलाश करे। 28 नवंबर और 1 दिसंबर को दूरसंचार विभाग के निर्देशों से यह बात भी झलकती है। पहला निर्देश ‘सिम बाइंडिंग’ को अनिवार्य करता है दूसरे निर्देश में, स्मार्टफोन निर्माताओं को मार्च, 2026 तक सभी नए उपकरणों में डिवाइस की प्रामाणिकता सत्यापित करने के लिए संचार साथी एप पहले से इंस्टॉल करना होगा। पहला निर्देश एक सुरक्षा पैच है जो वॉट्सएप/इंटरनेट मैसेजिंग उपयोगकर्ताओं को असुविधा पहुंचा सकता है, जबकि दूसरे निर्देश के पीछे एक डर है कि ‘अच्छे इरादों से किया गया काम भी गलत रास्ते पर ले जा सकता है।’

दूसरी तरफ इस बात की संभावना बनी रहती है कि इस एप का सरकारी निगरानी के लिए दुरुपयोग और उपयोगकर्ताओं को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ समय पहले आरोप लगाया गया था कि भारत में राजनीतिक विपक्ष, पत्रकारों और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने के लिए पेगासस सॉफ़्टवेयर का इस्तेमाल किया। हालांकि, उस मामले में साबित कुछ नहीं हुआ, पर उस परिघटना ने भय पैदा जरूर कर दिया है।

प्रेरणा

जब जिंदगी ने ‘ना’ कहा और किस्मत ने दरवाज़ा खोल दिया

ब्रायन एक्टन की कहानी किसी फिल्मी पटकथा की तरह लगती है—एक ऐसा युवक जो प्रतिभाशाली है, मेहनती है, पर दुनिया बार-बार उसे जवाब देती रहती है। सिलिकॉन वैली जैसे सपनों की नगरी में 2009 का साल उसके लिए उम्मीद और निराशा का अजीब-सा मिश्रण था। बड़े-बड़े दफ्तरों में घूमना, इंटरव्यू देना, कागज़ों में सपनों का वजन लेकर जाना—लेकिन हर बार लौटते वक्त हाथ में सिर्फ अस्वीकृति की चिट्ठी होती थी।

फेसबुक और ट्विटर—सोशल मीडिया के दो बड़े नाम, जिनके दफ्तरों में काम करना तकनीकी पेशेवरों का सपना होता था। ब्रायन ने भी आवेदन दिया, अपना अनुभव बताया, अपनी क्षमता साबित करने की कोशिश की, लेकिन दोनों ने एक ही जवाब दिया—“हम आपको नहीं ले सकते।” दूसरों के लिए यह केवल नौकरी न मिल पाने की घटना होती, लेकिन ब्रायन के लिए यह एक झटका था जिसने भीतर कुछ गहराई में बदलना शुरू किया।

उसने निराश होकर रोना नहीं चुना, न ही खुद को कम आँका। वह बाहर सड़क पर बैठा, अपने फ़ोन से ट्वीट किया—“फेसबुक ने मुझे ठुकरा दिया। अच्छा मौका था, लेकिन शायद कुछ और बेहतर मेरा इंतज़ार कर रहा है।” यह वाक्य उस समय एक मजबूरी का बहाना लग सकता था, लेकिन भविष्य की पटकथा इसी पंक्ति से लिखनी शुरू हो गई थी।

ठुकराए जाने के कुछ ही हफ्तों बाद उसकी मुलाकात जेन कौम से हुई—पुराना दोस्त, गहरी सोच वाला साथी, और वही इंसान जिसने ब्रायन की बेचैनी को समझा। दोनों ने कॉफी के कपों के बीच एक साधारण-सा सवाल उठाया—क्या लोगों को संदेश भेजने का तरीका और सरल, और सुरक्षित नहीं बनाया जा सकता? क्या एक ऐसा मंच नहीं हो सकता जहां न विज्ञापन हों, न ध्यान भटकाने वाली चीज़ें—बस एक सीधी, साफ और भरोसेमंद बातचीत?

इस सवाल से एक चिंगारी निकली, और उसी चिंगारी ने जन्म दिया व्हाट्सएप को।

शुरुआत में यह मात्र एक छोटा-सा एप था—स्टेटस अपडेट करने वाला। लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे इसमें मैसेजिंग की सुविधा जुड़ी, दुनिया ने इसे अपने दिल में जगह देना शुरू कर दिया। भारत से लेकर ब्राजील तक, अमेरिका से लेकर यूरोप तक—लोगों के फोन में यह एप एक आदत बन गया, फिर ज़रूरत बन गया और अंत में जीवनशैली का हिस्सा बन गया।

2014 में वही फेसबुक जिसने ब्रायन का आवेदन ठुकराया था, व्हाट्सएप को खरीदने के लिए उसके सामने बैठा था। सौदा इतिहास का हिस्सा बन गया—19 अरब डॉलर। वह क्षण सिर्फ ब्रायन की सफलता नहीं था, बल्कि यह प्रमाण था कि कभी-कभी दुनिया का ‘ना’ ईश्वर का ‘यहाँ से आगे बढ़ो’ भी हो सकता है। ब्रायन एक्टन की कहानी यह समझाती है कि अस्वीकृति कोई दरवाज़ा बंद नहीं करती, बल्कि हमें उस रास्ते पर मोड़ देती है जहां हमारी असली पहचान, असली क्षमता और असली मंज़िल हमारा इंतज़ार कर रही होती है। कभी-कभी जिंदगी को हमें गिराने के लिए नहीं, बल्कि हमारी चाल बदलने के लिए ‘ना’ कहना पड़ता है—और वही ‘ना’ एक दिन दुनिया बदल देने वाले ‘हाँ’ में बदल जाता है।

अनावश्यक नियमों की अधिकता, एमएसएमई को लेकर सामने आई रिपोर्ट में कई खुलासे

भारत लंबे समय से विश्व की सबसे तेज गति से वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है। इतनी तेज वृद्धि के बावजूद तमाम जानकार यह मानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी अपनी क्षमताओं से कम प्रदर्शन कर रही है। यानी भारतीय आर्थिकी और तेज गति से दौड़ने में सक्षम है, लेकिन इस राह में कुछ बाधाएं भी हैं। ऐसी ही एक बाधा नियमन एवं अनुपालन के बोझ से जुड़ी हुई है।

‘भारत में एमएसएमई विनिर्माण के लिए अनुपालनों की पड़ताल’ शीर्षक से प्रकाशित एक हालिया रिपोर्ट इसे रेखांकित भी करती है। इसके अनुसार किसी राज्य में सक्रिय एमएसएमई को साल भर में अनुपालन की करीब 1,456 कसौटियों पर खरा उतरना पड़ता है। इनमें से 998 कसौटियां तो काफी कड़ी होती हैं। साल भर के दौरान उन्हें 70 से अधिक अनुमतियां प्राप्त करनी होती हैं। करीब 48 वैधानिक रजिस्टर बनाने पड़ते हैं और करीब 59 प्रकार के विभिन्न निरीक्षणों की तैयारी करनी पड़ती है। मानो इतना ही काफी नहीं है।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 9,321 नियामकीय संशोधन हुए। देश में सक्रिय करीब साढ़े छह करोड़ एमएसएमई को इन बदलावों का सामना करना पड़ता है। इससे उनकी अनुपालन लागत बढ़ी होगी। एक इकाई पर साल भर में 13 से 17 लाख रुपये का बोझ बढ़ता है। पहले से ही सीमित संसाधनों वाले छोटे उद्यमों पर यह एक बड़ी आपदा जैसा है। याद रहे कि जीडीपी में 30 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखने वाले ये उद्यम रोजगार सृजन के बड़े माध्यम भी हैं। नियमन के मोर्चे पर इन प्रतिकूलताओं को दूर करने की दिशा में भारतीय रिजर्व बैंक ने 28 नवंबर को एक असाधारण पहल की है। उसने स्वेच्छा से अपने नियामकीय दायरे को 97 प्रतिशत तक घटा दिया है। यह गहरे नीतिगत बदलाव का संकेत है। यह कहना गलत होगा कि इस परिवर्तन में नीति आयोग की किसी उच्चस्तरीय समिति की भूमिका रही है। रिजर्व बैंक का यह कदम उसकी स्वयं की आंतरिक समीक्षा और नियामकीय सुव्यवस्था के प्रयासों का परिणाम है।

जहां तक नीति आयोग में पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता वाली समिति का प्रश्न है तो यह समिति लाइसेंस, परमिट, निरीक्षण प्रणालियों और अनुपालन बोझ जैसे गैर-वित्तीय नियमनों संबंधी सुधारों पर केंद्रित है। गौबा के नेतृत्व वाली समिति ने विश्वास आधारित एवं पारदर्शिता को प्रोत्साहन देने वाली नियामकीय प्रणाली का विचार सुझाया है। इसका उद्देश्य नियमित लाइसेंस, अनापत्ति प्रमाणपत्रों की आवश्यकता की समाप्ति, निरीक्षणों को मान्यता प्राप्त तीसरे पक्षों के लिए स्थानांतरित करने के साथ ही यह सुनिश्चित करना भी है कि प्रत्येक नियमन की अनुपालन लागत और उसे अमल में लाने के भार मूल्यांकन पर भी विचार करे। इसके पीछे मूल भावना यही है कि नियमन की मंशा प्रशासनिक अवरोध उत्पन्न करने के बजाय संरक्षण प्रदान करने की होनी चाहिए। नियमन के मोर्चे पर सुधार आर्थिक प्रदर्शन को सुधारने का आधार बनते हैं। इससे प्रबंधन के लिए आर्थिक बोझ घटने से लेकर समय एवं संसाधन भी बचते हैं। नियमों में स्थायित्व और पूर्वानुमान निवेश को लेकर बेहतर परिदृश्य तैयार करते हैं। सेमीकंडक्टर और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है, जहां प्रतिफल की अवधि अपेक्षाकृत कुछ लंबी खिंचती है। सुगम नियमन आर्थिक गतिविधियों को संगठित एवं औपचारिक बनाने को भी प्रोत्साहित करते हैं।

इस दिशा में गौबा समिति की अनुशंसाओं पर विचार करें तो इसमें आर्थिक स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी गई है। इसके अनुसार लाइसेंस और अनुमतियां संवेदनशील क्षेत्रों तक ही सीमित होनी चाहिए। जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, पर्यावरणीय जोखिम और सार्वजनिक स्वास्थ्य के समक्ष संकट जैसे मामले ही नियमन के दायरे में आने चाहिए। यह अनुशंसा उस मौजूदा व्यवस्था को बदलती है, जहां परिचालन से पहले ही किसी उद्यम एवं उद्यमी को परीक्षा से गुजरना पड़ता है। अगर लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती भी है तो उसकी प्रकृति स्थायी होनी चाहिए।

यदि उनमें कोई अंतर्निहित जोखिम न हों तो नवीनीकरण का प्रविधान भी आवश्यक न किया जाए। समिति की अनुंशसाओं पर गौर किया जाए तो ये ‘निरीक्षण राज’ को समाप्त करने पर जोर देती हैं। इसमें निरीक्षण का जिम्मा थर्ड पार्टी यानी तटस्थ निकाय पर छोड़ने की बात है। इससे हितों के टकराव के मामले घटेंगे। तकनीक आधारित निरीक्षण मानवीय हस्तक्षेप को भी कम करता है।

एक बेहतर नियामकीय व्यवस्था वही होती है जो राज्य को स्थिरता प्रदान करे। इस दिशा में नियामकीय संशोधनों में अनियमितता उचित नहीं। उन्हें नियमित अंतराल पर करते रहने के बजाय साल में एक या दो बार किया जाना ही उचित होगा। नियमन के स्तर पर समीक्षा और सुझाव की गुंजाइश भी विद्यमान होनी चाहिए। प्रत्येक नियम को मूर्त रूप देने से पहले उसका नियामक प्रभाव मूल्यांकन यानी आरआइए भी उतना ही आवश्यक है।

इससे जहां औद्योगिक इकाइयों के लिए अनुपालन लागत, तो वहीं सरकार के स्तर पर प्रवर्तन लागत को लेकर सुविधा बढ़ेगी। मौजूदा नियमों की भी चरणबद्ध रूप से समीक्षा की जाए ताकि उनमें किसी प्रकार के दोहराव की आशंका समाप्त हो सके। नियमों का आदर्श रूप में पालन किसी भी व्यवस्था के लिए आवश्यक होता है, लेकिन अनावश्यक एवं अनुचित दंड की व्यवस्था भी अहित ही अधिक करती है। जैसे फाइलिंग में देरी, लिपिकीय गलतियां और तकनीकी खामियों को सजा के मामले में कुछ राहत देना गलत नहीं होगा।

भारत में एमएसएमई के लिए 486 ऐसी धाराएं हैं, जिनमें कारावास तक की सजा हो सकती है। यह किसी भी प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था की तुलना में कहीं ज्यादा है। इस मोर्चे पर विसंगतियों को दूर करने के लिए व्यावहारिक कदम उठाए जाना आवश्यक ही नहीं, अपितु अनिवार्य हो चला है।

निःसंदेह नियामकीय परिदृश्य को सुगम बनाने की दिशा में गौबा समिति ने एक सार्थक पहल की है। यदि इन पर सही तरीके से अमल किया जा सके तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था को नियंत्रण-आधारित ढांचे से सिद्धांत-केंद्रित व्यवस्था में बदलेगा। यह नई व्यवस्था सुगम और नवाचार हितैषी भी होगी।

अभियान

एक छोटी-सी हरकत, एक बड़ी सीख: दादी की नज़र में पैर हिलाने का रहस्य

शाम की वह पुरानी दुनिया आज भी कई लोगों की यादों में बसी हुई है—मिट्टी की खुशबू, आँगन में जलता दीया, टीन की छत पर गिरते पत्तों की आवाज़, और खाट पर बैठी दादी, जिनकी आँखों में उम्र का धुंधलापन था लेकिन समझ की रोशनी अब भी वैसी ही तेज। घर के बच्चे खेलते-दौड़ते थककर बिस्तर पर बैठते और जैसे ही कोई बच्चा अपने पैरों को हिलाने लगता, दादी बिना किसी देरी के कहतीं—“ऐसे मत हिलाओ पैर शांत बैठो।” उस समय यह बस एक डांट लगती, पर जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, यह एहसास होता है कि इस साधारण-सी बात में अनुभव की कितनी गहरी नदी बहती है।

भारतीय परिवारों में हर छोटी हरकत का एक अर्थ होता था। दादी सिर्फ बच्चों को देखकर ही समझ जाती थीं कि किसके मन में कैसा तूफ़ान चल रहा है। वे जानती थीं कि पैर हिलाता बच्चा बाहर से भले हँसता हुआ लगे, पर उसके भीतर बेचैनी का कोई छुपा हुआ सिरा जरूर होगा। यह बेचैनी कभी किसी छोटे डर की होती, कभी किसी अनकही बात की, और कभी सिर्फ मन की दुनिया में उठती हलचल की। दादी को किसी मनोवैज्ञानिक की किताब की जरूरत नहीं थी—जीवन ने ही उन्हें वह सब पढ़ा दिया था जो किताबें बाद में लिखती हैं।

उनकी नजर में पैर हिलाना मन की अस्थिरता का संकेत था। बच्चा चाहे कितना भी भला और आज्ञाकारी हो, अगर वह बैठकर पैर हिला रहा है तो उसका मन कहीं और घूम रहा है। दादी जानती थीं कि मन को स्थिर किए बिना जीवन का कोई भी काम टिक नहीं सकता। इसलिए वे बच्चों को जल्दी ही सिखा देती थीं कि शरीर की स्थिरता मन की स्थिरता लाती है, और मन की स्थिरता जीवन में सफलता की नींव बनती है। उनके लिए यह सिर्फ एक आदत सुधारना नहीं, बल्कि चरित्र का बीज बोना था।

धर्म और परंपरा की भाषा में यह बात और भी सुंदर ढंग से कही जाती थी। घरों में यह विश्वास था कि पैर हिलाने से घर की ऊर्जा असंतुलित होती है, और यह अशुभ माना जाता है। कहा जाता था कि लक्ष्मी जी स्थिर घर में ही वास करती हैं—जहाँ संयम है, शांति है, और व्यवहार में गंभीरता है। जब कोई बच्चा या बड़ा बेचैनी से पैर हिलाता, तो बड़े-बुजुर्ग इसे भविष्य के दुर्भाग्य का संकेत भी मान लेते थे। यह मान्यताएँ भले तकलीफ़ देती लगें, पर उनके भीतर एक गहरी सामाजिक समझ छिपी होती थी—एक ऐसा घर जहाँ सब शांत, संतुलित और स्थिर हों, वही घर समृद्ध होता है।

समय बदलता गया, विज्ञान बढ़ा, मनोविज्ञान ने कई नए शब्द दिए, और धीरे-धीरे यह समझ सामने आई कि पैर हिलाना कई बार किसी आंतरिक तनाव, एंग्जायटी, थकान, आयरन की कमी, या रेस्टलेस लेग सिंड्रोम का संकेत भी हो सकता है। डॉक्टर कहते हैं कि अगर यह आदत लगातार हो तो इसका सीधा संबंध नर्वस सिस्टम की उलझनों से भी हो सकता है। लेकिन दादी के पास इन शब्दों का ज्ञान तो नहीं था, फिर भी वे समझ जाती थीं कि बच्चा भीतर से व्याकुल है। वे उसे स्थिर बैठने को कहकर उसकी उस अदृश्य बेचैनी को धीरे से शांत कर देती थीं।

मनोविज्ञान का एक और पहलू कहता है कि कई लोग तनाव को अवचेतन में छिपाने के लिए पैर हिलाते हैं। यह शरीर का वह तरीका है जिसमें मन के तूफ़ान का दबाव धीरे-धीरे पैरों की थरथराहट में बदलकर बाहर निकलता है। दादी इस थरथराहट को पढ़ लेती थीं। उन्हें पता होता था कि यह बच्चे की आदत नहीं बल्कि उसके मन का एक अनकहा संदेश है। इसलिए वे समय रहते इसे रोक देती थीं, ताकि यह बेचैनी उसकी पहचान ना बन जाए।

रातों को जब घर चुप होता, दादी कहानी सुनाते-सुनाते कहती थीं कि जीवन की सबसे बड़ी ताकत मन का संतुलन है। वे बच्चों को बताते कि एक व्यक्ति अगर बैठ नहीं सकता, शांत नहीं रह सकता, अपने शरीर को स्थिर नहीं रख सकता, तो उसका मन भी किसी दिशा में टिक नहीं पाएगा। और वह जीवन की राहों में बार-बार उलझ जाएगा। इसलिए वे छोटी उम्र से ही सिखाती थीं कि स्थिर बैठना सीखो, अपने शरीर को आदेश देना सीखो, क्योंकि जो अपने भीतर को नियंत्रित कर लेता है, वही दुनिया को जीत सकता है।

इसलिए जब आज हम सोचते हैं कि दादी क्यों कहती थीं—“पैर मत हिलाओ,” तो बहुत साफ तरह से समझ आता है कि उनकी बात सिर्फ तमीज़ की नहीं थी। वह शरीर की ऊर्जा, मन की लय, घर की शांति, व्यक्ति की आदतों और भविष्य के स्वभाव—इन सभी को एक साथ देखती थीं। वे जानती थीं कि छोटी हरकतें बड़े असर छोड़ती हैं। और यही वजह है कि उनकी उस हल्की डांट के पीछे छिपा हुआ अर्थ इतना बड़ा था कि आज भी यादों में गूंजता है।

दादी की वह आवाज़, वह सीख, वह ध्यान—सब मिलकर बताते हैं कि घर में बोली गई हर पुरानी बात सिर्फ परंपरा नहीं थी; वह पीढ़ियों तक सहेजा गया जीवन-दर्शन था, जिसे समझने में पूरी उम्र लग जाती है।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA

गांधीनगर लोकसभा सांसद और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की प्रोत्साहक उपस्थिति में 'सांसद खेल महोत्सव 2025' का समापन समारोह आयोजित

▸▸ 21 सितंबर से 5 दिसंबर के दौरान 'फिट युवा फॉर विकसित भारत' के सूत्र के साथ गांधीनगर लोकसभा सांसद खेल महोत्सव के तहत 9 विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित

▸▸ वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी की प्रोत्साहक उपस्थिति

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह :-

- ▸▸ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा पांच वर्ष पहले दिया गया 'सांसद खेल महोत्सव' के आयोजन का विचार आज वटवृक्ष बन गया
- ▸▸ हारने के बाद जीतने की सीख के साथ जुनून से आगे बढ़ने का गुण हमें हर क्षेत्र में आगे ले जाता है
- ▸▸ वर्ष 2014 से 2025 तक केंद्र सरकार का खेल क्षेत्र का बजट पांच गुना बढ़ा

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल :-

- ▸▸ कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजन के साथ गुजरात दुनिया का स्पोर्ट्स हब बनेगा
- ▸▸ सांसद खेल महोत्सव सामाजिक समरसता, समानता और क्षमता का अनूठा उदाहरण
- ▸▸ अहमदाबाद केवल देश ही नहीं, बल्कि पूरे एशिया की खेल राजधानी बनेगा

(जीएनएस)। गांधीनगर : गांधीनगर लोकसभा सांसद और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की प्रोत्साहक उपस्थिति में शुक्रवार शाम अहमदाबाद में 'सांसद खेल महोत्सव 2025' का समापन समारोह आयोजित हुआ।

वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, नारणपुरा में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी मौजूद रहे।

समापन समारोह में गांधीनगर लोकसभा सांसद और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह एवं उपस्थित महानुभावों के करकमलों से अंडर-17 और ओपन एज ग्रुप में कबड्डी, खो-खो और वॉलीबॉल प्रतियोगिता की विजेता टीमों को सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पांच वर्ष पहले सांसद खेल महोत्सव के आयोजन का विचार दिया था। यह विचार आज वटवृक्ष बन गया है। सांसद खेल महोत्सव के अंतर्गत देश में 300 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में लाखों खिलाड़ी खेल खेलने के साथ-साथ फिटनेस और स्वास्थ्य प्राप्त कर रहे हैं। इसके साथ ही, अनेक खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा विकसित करने का प्लेटफॉर्म मिला है, जिससे टैलेंट खोज की शुरुआत हुई है।

उन्होंने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने गुजरात में खेल महाकुंभ शुरू किया था, आज देश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश के युवाओं में खेल के प्रति जिज्ञासा पैदा करने के साथ ही सुविधा, प्रशिक्षण और प्रतिस्पर्धा की प्रेरणा दी है।

श्री शाह ने कहा कि व्यक्ति के जीवन में खेल का विशेष महत्व है। हारने के बाद जीतने की सीख के साथ जुनून के साथ आगे बढ़ने का गुण हमें हर क्षेत्र में आगे ले जाता है, साथ ही साथ विजेता खिलाड़ी को बिना अहंकारी हुए खेल भावना से आगे बढ़ने की शिक्षा देता है।

उन्होंने गांधीनगर लोकसभा में हुए महोत्सव की जानकारी देते हुए कहा कि तीन चरणों में आयोजित खेलोत्सव में 1.57 लाख से अधिक खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें 87 हजार पुरुष और 70 हजार महिला खिलाड़ी शामिल थे। उन्होंने महिलाओं से अपील की कि वे आगामी समय में अधिक से अधिक संख्या में पंजीकरण कराएं।

उन्होंने 8500 विजेता खिलाड़ियों को बधाई देने के साथ ही पराजित खिलाड़ियों का आह्वान किया कि वे जिजीविषा और महत्वाकांक्षा को जीवन का प्रेरणास्रोत बनाकर आगे बढ़ें।

केंद्रीय गृह मंत्री ने आणंद में 59 हजार खिलाड़ियों के पंजीकरण के लिए पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने सांसदों से जो अपील की थी, वह आज युवाओं के लिए मार्गदर्शक बन गई है।

उन्होंने कहा कि खेल के जरिए अनुशासन, ध्येय, टीम भावना और खेल भावना जैसे गुणों का विकास होता है। इसके साथ ही, सांसद खेल महोत्सव से प्रतिभा की पहचान और स्व-परिचय के अलावा फिट इंडिया मूवमेंट और नशा मुक्त भारत अभियान को आगे बढ़ाने का काम भी होता है।

श्री शाह ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश के खिलाड़ियों को उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं। वर्ष 2014 में केंद्र सरकार का खेल क्षेत्र का बजट 800 करोड़ रुपए था, जो 2025 में पांच गुना बढ़कर 4000 करोड़ रुपए हो गया है। उन्होंने कहा कि देश में सुनियोजित स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य सुविधाओं के कारण विभिन्न महत्वपूर्ण प्रतियोगिताओं में भारत के मैडलों की संख्या भी बढ़ गई है।

उन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ियों द्वारा जीते गए मेडल की चर्चा करते हुए कहा कि वर्ष 2014 में आयोजित कॉमनवेल्थ खेलों में हमारे खिलाड़ियों ने 15 मेडल जीते थे, जिनकी संख्या बढ़कर 2018 में 26 और 2022 में 22 हो गई। एशियाई खेलों में हमारे खिलाड़ियों ने पहले के 57 मेडल के मुकाबले 107 मेडल जीते। जबकि पैरा एशियन गेम्स में पहले 33 मेडल थे, जो बढ़कर 111 हो गए।

श्री शाह ने उम्मीद जताई कि जब भारत में ओलंपिक खेल आयोजित होंगे तब हमारा स्थान पदक तालिका में शीर्ष पांच में होगा। उन्होंने उपस्थित सभी लोगों से व्यसन मुक्त रहने और अधिक से अधिक पौधरोपण करके ग्रीन कवर को बढ़ाने में अपना योगदान देने की अपील की।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के सफल प्रयासों के परिणामस्वरूप अहमदाबाद को 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करने का गौरव मिला है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम देश और राज्य में स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव देख रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजन के साथ ही गुजरात दुनिया का स्पोर्ट्स हब बनेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में गुजरात में 'खेले ते खिले' यानी जो खेलेगा, वह खिलेगा के मंत्र के साथ खेल महाकुंभ की शुरुआत की थी। खेल महाकुंभ ने राज्य के गांव-गांव से लेकर शहरों तक के युवाओं को खेल के प्रति प्रोत्साहित करने के साथ-साथ राज्य की खेल संस्कृति को एक नई दिशा दी है। प्रधानमंत्री बनने के बाद श्री नरेन्द्र मोदी ने इसी मॉडल को 'खेलो इंडिया' के जरिए देश में स्थापित किया है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र में सांसद खेल महोत्सव आयोजित करने की प्रेरणा दी है। आज सांसद खेल महोत्सव इवेंट एक महत्वपूर्ण खेल इवेंट और फिट इंडिया मूवमेंट की संवाहक बन गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के निर्माण के लिए नशा मुक्त भारत के निर्माण की बात कही है। सांसद खेल महोत्सव के कारण आज समाज के युवा खेलकूद की ओर आकर्षित हुए हैं। यह खेल महोत्सव समाज के हर वर्ग, हर क्षेत्र और हर क्षमता के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि सभी एक साथ विभिन्न खेलों में हिस्सा लेकर सामाजिक समरसता, समानता और क्षमता का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।

गांधीनगर सांसद खेल महोत्सव की बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री अमित शाह के गांधीनगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 9 से 60 वर्ष तक की उम्र के कुल 1,50,000 खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में हिस्सा लिया, जिनमें से 8000 से अधिक खिलाड़ी विभिन्न खेलों में विजेता बने हैं। उन्होंने कहा कि श्री अमित शाह ने गांधीनगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र को सबसे हरा-भरा निर्वाचन क्षेत्र बनाने के संकल्प के साथ ही इसका भी विशेष ध्यान रखा है कि उनके निर्वाचन क्षेत्र के नागरिक फिट इंडिया मूवमेंट के एंबेसडर बने और स्वस्थ एवं तंदुरुस्त रहें।

उन्होंने कहा कि श्री शाह के मार्गदर्शन में अहमदाबाद और गांधीनगर में बड़े पैमाने पर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है। वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स उनके विजन का उत्कृष्ट उदाहरण है। 2036 तक अहमदाबाद में लगभग 13 अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का आयोजन होने वाला है। ऐसे में आने वाले दिनों में अधिक से अधिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा। अहमदाबाद अब केवल देश की ही नहीं, बल्कि पूरे एशिया की खेल राजधानी के रूप में उभरकर आएगा।

मुख्यमंत्री ने विकसित भारत के निर्माण में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए पांच प्रणों में से एक नागरिक धर्म का पालन करके फिटनेस को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का सभी से अनुरोध किया।

उल्लेखनीय है कि 21 सितंबर से 05 दिसंबर के दौरान 'फिट युवा फॉर विकसित भारत' के सूत्र के साथ गांधीनगर लोकसभा सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें मल्लखंभ, एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो-खो, स्विमिंग, बैडमिंटन, शतरंज और योगासन सहित कुल 9 खेलों में खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। समापन समारोह में सांसद खेल महोत्सव 2025 की विस्तृत जानकारी देने वाली एक ऑडियो-वीडियो फिल्म भी प्रदर्शित की गई।

सांसद खेल महोत्सव 2025 के समापन समारोह में ऊर्जा और पेट्रोलियम मंत्री श्री ऋषिकेश पटेल, खेल एवं युवा सेवा राज्य मंत्री डॉ. जयरामभाई गामित, अहमदाबाद की महापौर श्रीमती प्रतिभा जैन, गांधीनगर की महापौर श्रीमती मीराबेन पटेल, अहमदाबाद शहर और ग्रामीण के विधायक तथा अहमदाबाद और गांधीनगर जिला पंचायतों के अध्यक्ष और अग्रणी श्री प्रेरक शाह, श्री शिल्पाबेन पटेल, श्री शैलेषभाई दावड़ा, श्री अनिलभाई पटेल, डॉ. आशिषभाई दवे उपस्थित थे।

वडोदरा मंडल के प्रयासों से वासद - कठाणा खंड पर 7 दिसंबर से फिर दौड़ेगी डेमू ट्रेन

KATHANA

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल द्वारा वासद - कठाणा खंड पर डेमू सेवा को 7 दिसंबर से रि-इंट्रोडूयूस किया जा रहा है। गुजरात में इस वर्ष आयी बाढ़ से इस क्षेत्र के सड़क मार्ग के साथ साथ इस रेल खंड को भी बहुत नुकसान हुआ था। माननीय जनप्रतिनिधिओं एवं यात्रिओं के मांग पर तत्परता दिखाते हुए वडोदरा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके के निर्देशन में वासद - कठाना खंड पर यात्री सेवा को बहाल किया जा रहा है। पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के जनसम्पर्क अधिकारी श्री अनुभव सक्सेना द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार कोविड काल में यात्रिओं की स्वास्थ्य सुरक्षा को देखते हुए भारतीय रेल द्वारा यात्री सेवाओं को बंद किया गया था, जिसे कोविड काल के बाद चरणबद्ध रूप से बहाल किया जा रहा है। गुजरात में इस वर्ष आयी बाढ़ से इस क्षेत्र के सड़क मार्ग के साथ साथ इस रेल खंड को भी बहुत नुकसान हुआ था। रेलवे ट्रैक के साथ साथ इस खंड के स्टेशनों की बिल्डिंग की भी क्षति हुई थी। सड़क मार्ग द्वारा आवागमन में जनता को आ रही दिक्कतों को देखते हुए जनप्रतिनिधियों की मांग थी कि जनता के लिए ट्रेन सेवा यात्रा का सुगम माध्यम है,जिससे समय की भी बचत होती है। यह ट्रेन सेवा जल्द उपलब्ध कराई जाये, जिससे इस क्षेत्र के व्यापारिओं, छात्रों आदि को सुविधा उपलब्ध हो सके जो व्यापार या पढ़ाई के लिए दूसरे स्थान विशेषकर वडोदरा की यात्रा करते हैं।

माननीय जनप्रतिनिधिओं की मांग पर अमल करते हुए एवं यात्रिओं के मांग पर तत्परता दिखाते हुए विपरीत परिस्थिति के बावजूद वडोदरा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके के निर्देशन में अधिकारिओं एवं रेलकर्मियों की मेहनत एवं प्रयासों से वासद - कठाना खंड पर ट्रेन सेवा को रि-इंट्रोडूयूस किया जा रहा है।

बाढ़ से प्रभावित एवं डैमेज खंड पर बैलास्ट फाइलिंग, टैंपरिंग जैसे ट्रैक वर्क किये गए हैं। लेवल क्रासिंग रिपेयरिंग वर्क के अंतर्गत लिफ्टिंग बैरियर की रिपेयरिंग की गयी एवं रोडसाइड बोर्डों को लगाकर अप्रोच रोड को दुरुस्त किया गया। स्टेशन पर कवरशेड, प्लेटफार्म, एप्रोच रोड की मरम्मत के साथ साथ स्टेशन भवन की प्लास्टरिंग एवं रिपेरिंग जैसे कार्य कर इससे ट्रेन परिचालन के लिए उपयुक्त बनाया गया।

पश्चिम रेलवे का वडोदरा मंडल यात्रिओं को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए हमेशा प्रतिबध्द है।

6 से 9 दिसंबर तक साबरमती-योगनगरी ऋषिकेश योगा एक्सप्रेस मेरठ सिटी तक जाएगी

(जीएनएस)। उत्तर रेलवे के देहारादून स्टेशन पर लोको पिट साइडिंग कार्य हेतु ब्लॉक के कारण साबरमती-योगनगरी ऋषिकेश योगा एक्सप्रेस मेरठ सिटी और योगनगरी ऋषिकेश के बीच आंशिक निरस्त रहेगी। जो इस प्रकार है:

6 दिसंबर से 9 दिसंबर 2025 तक साबरमती से चलने वाली ट्रेन संख्या 19031 साबरमती-योगनगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस मेरठ सिटी स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी, इस प्रकार यह ट्रेन मेरठ सिटी और योगनगरी ऋषिकेश के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।

7 दिसंबर से 10 दिसंबर 2025 तक ट्रेन संख्या 19032 योगनगरी ऋषिकेश-साबरमती एक्सप्रेस योगनगरी ऋषिकेश के स्थान पर मेरठ सिटी से प्रस्थान करेगी, इस प्रकार यह ट्रेन योगनगरी ऋषिकेश-मेरठ सिटी के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।

ट्रेनों के समय, ठहराव और संरचना से सम्बंधित विस्तृत जानकारी के लिए यात्री www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

आगामी VGRC, राजकोट में गुजरात की ब्लू इकोनॉमी और सतत तटीय विकास पर होगा शानदार प्रदर्शन

▸▸ वर्ष 2024–25 में समुद्री मत्स्य उत्पादन 7,64,343 मीट्रिक टन रहा, जो 2023–24 की तुलना में 14% से अधिक है

▸▸ सौराष्ट्र क्षेत्र ने 2024–25 में 5,42,333 मीट्रिक टन और कच्छ ने 67,547 मीट्रिक टन उत्पादन दर्ज किया

▸▸ सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र गुजरात के कुल समुद्री मत्स्य उत्पादन में लगभग 80% योगदान देते हैं

(जीएनएस)। गांधीनगर : माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 'समुद्र से समृद्धि' के विज़न को साकार करने के लिए, गुजरात अपने मछली पालन क्षेत्र की तेज़ प्रगति के माध्यम से भारत की ब्लू इकोनॉमी को लगातार नई दिशा दे रहा है। 2,340.62 किलोमीटर लंबी भारत की सबसे विशाल समुद्री तटरेखा वाले गुजरात ने देश की समुद्री समृद्धि में एक अग्रणी योगदानकर्ता के रूप में अपनी पहचान मजबूत की है। सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र गुजरात के कुल मत्स्य उत्पादन का लगभग 80 प्रतिशत योगदान करते हैं और इस प्रगति के केंद्र में बने हुए हैं।

भारत वर्तमान में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, जो वैश्विक उत्पादन में 8 प्रतिशत का योगदान देता है। मत्स्य क्षेत्र में अंतर्देशीय व समुद्री मत्स्य पालन, एक्वाकल्चर, सीफूड प्रोसेसिंग, मार्केटिंग और निर्यात शामिल हैं, और इसे एक सूर्योदय क्षेत्र के रूप में मान्यता मिली है। इसके साथ ही यह क्षेत्र मत्स्य उपकरण निर्माण, शोध, शिक्षा और प्रशासनिक प्रबंधन को भी समाहित करता है। यह क्षेत्र लगभग 3 करोड़ व्यक्तियों को आजीविका प्रदान करता है।

राज्य के अधिकारी बताते हैं कि गुजरात देश का दूसरा सबसे बड़ा समुद्री मत्स्य उत्पादक राज्य है। पिछले चार वर्षों में राज्य ने औसतन लगभग 9.30 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक मछली उत्पादन दर्ज की है। वित्त वर्ष 2025–26 के लिए राज्य द्वारा 8,40,069 मीट्रिक टन समुद्री मछली उत्पादन और 3,31,284 मीट्रिक टन अंतर्देशीय उत्पादन का अनुमान लगाया गया है, जिससे कुल उत्पादन लगभग 11,71,353 मीट्रिक टन रहने का आकलन है।

इसी दौरान, सौराष्ट्र क्षेत्र अपने आठ प्रमुख मत्स्य-उत्पादक जिलों के साथ गुजरात के कुल मछली उत्पादन में 70% से अधिक का योगदान देता है। राज्य का सबसे बड़ा जिला कच्छ, राज्य के कुल मछली उत्पादन का लगभग 9% हिस्सा रखता है। वर्ष 2024–25 (अक्टूबर 2024 से सितंबर 2025) में गुजरात ने 7,64,343 मीट्रिक टन समुद्री मछली उत्पादन दर्ज किया, जिसमें अकेले सौराष्ट्र ने 5,42,333 मीट्रिक टन योगदान दिया, जबकि कच्छ क्षेत्र ने 67,547 मीट्रिक टन उत्पादन किया।

सौराष्ट्र और कच्छ मिलकर गुजरात के कुल समुद्री मछली उत्पादन का लगभग 80% हिस्सा प्रदान करते हैं। वर्ष 2024–25 में राज्य के समुद्री मछली उत्पादन में 14% से अधिक की वृद्धि भी दर्ज हुई, जो 2023–24 के 7,04,828 मीट्रिक टन से बढ़कर 7,64,343 मीट्रिक टन पर पहुंच गया।

आगामी VGRC का आयोजन जनवरी 2026 के द्वितीय सप्ताह में राजकोट में किया जाएगा, जो गुजरात में ब्लू इकोनॉमी और सतत तटीय विकास और समुद्री समृद्धि के प्रति प्रतिबद्धता को पुनः दृढ़ करता है। यह सम्मेलन गुजरात के मत्स्य क्षेत्र की उपलब्धियों और भविष्य की संभावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करेगा।

सम्मेलन में भारत की ब्लू इकोनॉमी को नवाचार, स्थिरता और समावेशी विकास के माध्यम से आगे बढ़ाने में गुजरात की अहम भूमिका को भी रेखांकित किया जाएगा। इस आयोजन में नीति-निर्माताओं, उद्योग जगत के नेताओं, विशेषज्ञों और विभिन्न हितधारकों को एक साथ लाया जाएगा, ताकि उभरती तकनीकों, श्रेष्ठ तौर-तरीकों और निवेश के अवसरों पर व्यापक चर्चा हो सके।

पश्चिम रेलवे चलाएगी चार जोड़ी स्पेशल ट्रेनें

(जीएनएस)। यात्रियों की सुविधा और यात्रा मांग को पूरा करने के उद्देश्य से, पश्चिम रेलवे द्वारा मुंबई सेंट्रल – भिवानी, मुंबई सेंट्रल – शकूर बस्ती, बांद्रा टर्मिनस – दुर्गापुरा एवं वलसाड – बिलासपुर स्टेशनों के बीच विशेष किराये पर स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इन ट्रेनों का विवरण इस प्रकार है:

1. ट्रेन संख्या 09001/09002 मुंबई सेंट्रल – भिवानी सुपरफास्ट स्पेशल (द्विसाप्ताहिक)
[14 फेरे]

ट्रेन संख्या 09001 मुंबई सेंट्रल – भिवानी सुपरफास्ट स्पेशल प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार को 10.30 बजे मुंबई सेंट्रल से प्रस्थान करेगी और अगले दिन 13.00 बजे भिवानी पहुंचेगी। यह ट्रेन 09 दिसम्बर से 30 दिसम्बर, 2025 तक चलेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09002 भिवानी – मुंबई सेंट्रल सुपरफास्ट स्पेशल प्रत्येक बुधवार एवं शनिवार को 14.35 बजे भिवानी से प्रस्थान करेगी और अगले दिन 16.30 बजे मुंबई सेंट्रल पहुंचेगी। यह ट्रेन 10 दिसम्बर से 31 दिसम्बर, 2025 तक चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, पालघर, वापी, वलसाड, सूरत, भरूच, वडोदरा, रतलाम, मंदसौर, नीमच, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बिजयनगर, नसीराबाद, अजमेर, किशनगढ़, जयपुर, गांधी नगर जयपुर, बांदीकुई, अलवर, रेवाड़ी, कोसली और चरखी दादरी स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में एसी-3 टियर, स्लीपर क्लास और जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।

2. ट्रेन संख्या 09003/09004 मुंबई सेंट्रल – शकूर बस्ती सुपरफास्ट स्पेशल (32 फेरे)

ट्रेन संख्या 09003 मुंबई सेंट्रल – शकूर बस्ती स्पेशल मंगलवार एवं शुक्रवार को छोड़कर सभी दिनों में 10.30 बजे मुंबई सेंट्रल से प्रस्थान करेगी और अगले दिन 08.00 बजे शकूर बस्ती पहुंचेगी। यह ट्रेन 08 दिसम्बर से 29 दिसम्बर, 2025 तक चलेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09004 शकूर बस्ती – मुंबई सेंट्रल स्पेशल बुधवार एवं शनिवार को छोड़कर सभी दिनों में 10.15 बजे शकूर बस्ती से प्रस्थान करेगी और अगले दिन 10.30 बजे मुंबई सेंट्रल पहुंचेगी। यह ट्रेन 09 दिसम्बर से 30 दिसम्बर, 2025 तक चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, पालघर, वापी, वलसाड, सूरत, भरूच, वडोदरा, रतलाम, नागदा, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, हिंडौन सिटी, भरतपुर, मथुरा, कोसी कलां एवं दिल्ली सफदरजंग स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में एसी-3 टियर, स्लीपर क्लास और जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।

3. ट्रेन संख्या 09730/09729 बांद्रा टर्मिनस – दुर्गापुरा सुपरफास्ट स्पेशल (02 फेरे)

ट्रेन संख्या 09730 बांद्रा टर्मिनस – दुर्गापुरा सुपरफास्ट स्पेशल सोमवार, 08 दिसम्बर 2025 को 10.00 बजे बांद्रा टर्मिनस से प्रस्थान करेगी और अगले दिन 05.30 बजे दुर्गापुरा पहुंचेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09729 दुर्गापुरा – बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट स्पेशल रविवार, 07 दिसम्बर 2025 को 12.25 बजे दुर्गापुरा से प्रस्थान करेगी और अगले दिन 07.00 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, पालघर, वापी, वलसाड, नवसारी, सूरत, भरूच, वडोदरा, रतलाम, नागदा, भवंनी मंडी, रामगंज मंडी, कोटा, सवाई माधोपुर एवं बनस्थली निवाई स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में फर्स्ट एसी, एसी-2 टियर, एसी-3 टियर, स्लीपर क्लास और जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।

4. ट्रेन संख्या 08244/08243 वलसाड – बिलासपुर स्पेशल (08 फेरे)

ट्रेन संख्या 08244 वलसाड – बिलासपुर स्पेशल प्रत्येक शुक्रवार को 16.50 बजे वलसाड से प्रस्थान करेगी और अगले दिन 13.50 बजे बिलासपुर पहुंचेगी। यह ट्रेन 19 दिसम्बर 2025 से 09 जनवरी 2026 तक चलेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 08243 बिलासपुर – वलसाड स्पेशल प्रत्येक गुरुवार को 16.00 बजे बिलासपुर से प्रस्थान करेगी और अगले दिन 13.50 बजे वलसाड पहुंचेगी। यह ट्रेन 18 दिसम्बर 2025 से 08 जनवरी 2026 तक चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में भेस्तान, चलथान, नंदुरबार, अमलनेर, जलगांव, भुसावल, मलकापुर, अकोला, बड़नेरा, वर्धा, नागपुर, गोंदिया, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर एवं भाटापारा स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में एसी-2 टियर, एसी-3 टियर, स्लीपर क्लास और जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।

ट्रेन संख्या 09003 एवं 09730 की बुकिंग 06.12.2025 से, ट्रेन संख्या 09001 की बुकिंग 07.12.2025 से तथा ट्रेन संख्या 08244 की बुकिंग 08.12.2025 से सभी पीआरएस काउंटरों एवं आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के ठहराव, समय एवं संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

भावनगर टर्मिनस स्टेशन यार्ड में पिट लाइन के कार्य हेतु ब्लॉक लिए जाने के कारण भावनगर मंडल की कुछ ट्रेनें प्रभावित होंगी

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल के भावनगर टर्मिनस स्टेशन यार्ड में पिट लाइन संख्या–2 के मरम्मत कार्य हेतु 08 दिसंबर, 2025 से आगामी 45 दिनों तक ब्लॉक किए जाने के कारण कुछ ट्रेनों के संचालन में अस्थायी परिवर्तन किए गए हैं। इस अवधि के दौरान ट्रेनों का निरस्तीकरण, शॉर्ट टर्मिनेशन/ओरिजिनेशन तथा पुनर्निर्धारण किया गया है। यात्रियों से अनुरोध है कि यात्रा से पूर्व संबंधित जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी के अनुसार प्रभावित ट्रेनों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:

निरस्त (Cancel) की जाने वाली ट्रेनें (दैनिक – दो-दो फेरे)

दिनांक 08.12.2025 से निम्न ट्रेनें निरस्त (Cancel) रहेंगी –

1. 59228/59233 (भावनगर–सुरेंद्रनगर–भावनगर)
2. 59267/59268 (भावनगर–पालिताना–भावनगर)
3. 59269/59270 (भावनगर–पालिताना–भावनगर)

4. 59229/59230 (भावनगर–बोटाद–भावनगर)
5. 59204/59271 (भावनगर–बोटाद–भावनगर)
6. 59235/59236 (धोला-महुवा-धोला)
7. 09529/09530 (धोला–भावनगर–धोला टीओडी स्पेशल)

शॉर्ट टर्मिनेशन/ओरिजिनेशन (Short Termination/Origination)

1. ट्रेन संख्या 19209 (भावनगर–ओखा) प्रत्येक सोमवार, बुधवार, गुरुवार एवं रविवार को राजकोट स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी (सप्ताह में 04 फेरे)। अर्थात् यह ट्रेन शुक्रवार, शनिवार और मंगलवार को भावनगर टर्मिनस से चलकर ओखा तक जाएगी, बाकी दिन (रविवार, सोमवार, बुधवार और गुरूवार) भावनगर से चलकर राजकोट तक जाएगी।
2. ट्रेन संख्या 19210 (ओखा–भावनगर) प्रत्येक सोमवार, बुधवार, गुरुवार एवं रविवार को राजकोट स्टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी (सप्ताह में 04 फेरे)। यह ट्रेन सोमवार, बुधवार, गुरुवार एवं रविवार को राजकोट स्टेशन से प्रस्थान करेगी अर्थात् यह ट्रेन राजकोट से चलकर भावनगर तक जाएगी। यह ट्रेन मंगलवार, शुक्रवार एवं शनिवार को अपने निर्धारित समयानुसार ओखा से चलकर भावनगर तक जाएगी।

उल्लेखनीय है कि उपरोक्त किसी भी ट्रेन के समय में परिवर्तन नहीं किया गया है। उपरोक्त दोनों ट्रेनें अपने निर्धारित समयानुसार हीं चलेंगी।

पुनर्निर्धारित ट्रेनें (Rescheduled Trains)

1. ट्रेन संख्या 12972 (भावनगर–बान्द्रा टर्मिनस) 08.12.2025 से प्रत्येक मंगलवार एवं गुरुवार को 2 घंटा 30 मिनट विलंब से चलेगी।
2. ट्रेन संख्या 59558 (भावनगर–वेरावल) प्रत्येक शनिवार को अपने निर्धारित समय से 3 घंटा विलंब से चलेगी।
3. ट्रेन संख्या 20966 (भावनगर–गांधीग्राम) प्रत्येक रविवार एवं गुरुवार को 30 मिनट विलंब से चलेगी।
4. ट्रेन संख्या 19271 (भावनगर–हरिद्वार) प्रत्येक गुरुवार को 3 घंटा विलंब से चलेगी।

उक्त सभी परिवर्तन 45 दिनों तक या पिट लाइन संख्या–2 के पूर्ण रूप से परिचालन में आने तक लागू रहेंगे। आम जनता को विभिन्न माध्यमों से इसकी व्यापक जानकारी दी जा रही है।

यात्रियों से अनुरोध है कि असुविधा से बचने के लिए यात्रा से पूर्व संबंधित स्टेशन अथवा रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in से अद्यतन जानकारी प्राप्त करें।

देश के ग्रोथ इंजन गुजरात की एक और उपलब्धि प्रति व्यक्ति आय पहली बार 3 लाख रुपए के पार

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन और मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में गुजरात 8.42% की वृद्धि दर के साथ बना शीर्ष राज्य

(जीएनएस)। गांधीनगर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन और गुजरात में उनके द्वारा शुरू की गई विकास यात्रा को मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गुजरात की प्रति व्यक्ति आय पहली बार 3 लाख रुपए को पार कर गई है, और राज्य ने आर्थिक प्रगति में नए मानदंड स्थापित किए हैं। इतना ही नहीं, सितंबर में समाप्त चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि 8.2 फीसदी दर्ज की गई है, जिसमें गुजरात का मजबूत प्रदर्शन रहा है। गुजरात के इस निरंतरतापूर्ण प्रदर्शन के कारण ही उसने भारत की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में अपना स्थान बरकरार रखा है और इसीलिए उसे भारत का ग्रोथ इंजन कहा जाता है।

ताजा आंकड़ों के अनुसार गुजरात ने पिछले दशक में असाधारण वृद्धि हासिल की है। 2023-24 में 24.62 लाख करोड़ रुपए के सकल राज्य घरेलू उत्पादन (जीएसडीपी) के साथ, गुजरात ने अब महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के बाद भारत की शीर्ष पांच अर्थव्यवस्थाओं में स्थान बना लिया है।

उल्लेखनीय है कि वृद्धि को सटीक तौर पर समझने के लिए दीर्घकालिक प्रदर्शन को वास्तविक दृष्टि यानी स्थित कीमतों पर मापा जाता है। यह मुद्रा स्फीति के प्रभाव को दूर करता है और उत्पादन एवं आर्थिक गतिविधियों में वास्तविक वृद्धि को दर्शाता है। इस आधार पर, गुजरात ने 2012-13 से 2023-24 की अवधि के दौरान 8.42 फीसदी की औसत वृद्धि दर हासिल की है, जो 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक की अर्थव्यवस्था वाले सभी बड़े राज्यों में सबसे अधिक है। इसके साथ ही, गुजरात ने कर्नाटक (7.69%) और तमिलनाडु (6.29%) को भी पीछे

छोड़ दिया है।

ऐसे समय में, जब बड़ी अर्थव्यवस्थाएं आम तौर पर संरचनात्मक संतृप्ति (स्ट्रक्चरल सैचुरेशन) के कारण सुस्त पड़ जाती हैं, गुजरात अपने मजबूत औद्योगिक आधार, निवेश-अनुकूल माहौल, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और कुशल नीतियों के कारण विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है।

जीएसडीपी के नए आंकड़ें यह बताते हैं कि गुजरात की अर्थव्यवस्था विभिन्न क्षेत्रों के मजबूत प्रदर्शन के कारण तेजी से बदल रही है। राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने 2023-24 में 7.43 लाख करोड़ रुपए का योगदान

दिया, जो सकल राज्य मूल्य वर्धन (जीएसवीए) का लगभग एक तिहाई हिस्सा है। इसके अलावा, कंस्ट्रक्शन और यूटिलिटी क्षेत्र का योगदान 2.31 लाख करोड़ रुपए और व्यापार, परिवहन, वित्तीय सेवाओं और रीयल एस्टेट जैसे क्षेत्रों का योगदान 7.81 लाख करोड़ रुपए रहा। वहीं, कृषि, वन और मत्स्यपालन जैसे पारंपरिक क्षेत्रों ने 3.69 लाख करोड़ रुपए का योगदान दिया, जिससे राज्य का समावेशी विकास सुनिश्चित हुआ है।

कुल मिलाकर, स्थिर मूल्यों पर गुजरात का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 2011-12 में 6.16 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2023-24 में 24.62 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो एक दशक में लगभग चार गुनी वृद्धि दर्शाता है।

राज्य की प्रति व्यक्ति आय पहली बार 3 लाख रुपए के पार

गुजरात ने आर्थिक क्षेत्र में एक नया मील का पत्थर स्थापित किया है और प्रति व्यक्ति आय पहली बार 3 लाख रुपए को पार कर गई है। गुजरात 3,00,957 रुपए प्रति व्यक्ति आय के साथ भारत की शीर्ष पांच सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है। यह आंकड़ा महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से अधिक है, जो राज्य की उच्च श्रम उत्पादकता और व्यापक आर्थिक भागीदारी को दर्शाता है। मजबूत दीर्घकालिक विकास, उच्च प्रति व्यक्ति आय और लगातार बढ़ते आर्थिक आधार के साथ, गुजरात सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था बन गया है। 8.42% की वास्तविक वृद्धि दर के साथ गुजरात सुशासन, लचीलेपन और रणनीतिक कार्यान्वयन के एक मॉडल के रूप में उभरा है।

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह और मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद शॉपिंग फेस्टिवल का उद्घाटन किया

श्री अमित शाह और श्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद शॉपिंग फेस्टिवल कार्निवल परेड को हरी झंडी दिखाई

(जीएनएस)। गांधीनगर : केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह और मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने शुक्रवार को अहमदाबाद महानगर पालिका और राज्य सरकार के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 'अहमदाबाद शॉपिंग फेस्टिवल (एएसएफ) 2025-26' का शानदार शुभारंभ किया।

इस फेस्टिवल के शुभारंभ अवसर पर श्री अमित शाह और श्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद शॉपिंग फेस्टिवल कार्निवल परेड को हरी झंडी दिखाई और शॉपिंग फेस्टिवल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री श्री ऋषिकेश पटेल भी उपस्थित रहे।

केंद्रीय गृह मंत्री एवं मुख्यमंत्री ने शॉपिंग फेस्टिवल के विभिन्न स्टॉलों का दौरा किया। महानुभावों ने स्वदेशी वस्तुओं की खरीदारी की और डिजिटल पेमेंट कर लोगों को प्रोत्साहित किया।

अहमदाबाद की महापौर श्रीमती प्रतिभा जैन, अहमदाबाद शहर के सभी विधायक और पार्षदगण, उप महापौर श्री जतिन पटेल, मनपा स्थाई समिति के अध्यक्ष श्री देवांग दाणी, शासक पक्ष के नेता श्री गौरांग प्रजापति, सचेतक श्रीमती शीतल डागा और चीफ कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स श्री राजीव टोपनो, मनपा आयुक्त श्री बंछानिधि पाणि, मनपा की विभिन्न समितियों के चेयरमैन, शहर अध्यक्ष श्री प्रेरक शाह और अहमदाबाद महानगर पालिका के अधिकारी एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि 5 दिसंबर, 2025 से 16

जनवरी, 2026 तक चलने वाला यह रिटेल, लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट का विशाल महोत्सव प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'वोकल फॉर लोकल' के संकल्प को साकार करने के साथ ही शहर के व्यापार और पर्यटन क्षेत्र में एक नई ऊर्जा भरेगा। 'स्वदेशी विद ग्लोबल अपील' की थीम पर आधारित इस फेस्टिवल के दूसरे संस्करण के लिए नगरजनों में उत्साह देखने को मिल रहा है।

इस वर्ष अहमदाबाद शॉपिंग फेस्टिवल (एएसएफ) के अंतर्गत शहर के 6 मुख्य शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट और 12 से अधिक हॉटस्पॉट जोन तैयार किए गए हैं, जिनमें सिंधु भवन रोड, सीजी रोड, निकोल मॉडर्न स्ट्रीट, कांकरिया-रामबाग रोड, वस्त्रापुर, प्रहलाद नगर, साइंस सिटी, रिवरफ्रंट, लॉ गार्डन और माणेक चौक सहित अन्य क्षेत्र एवं शहर के अग्रणी मॉल शामिल हैं। पूरे शहर में शॉपिंग, मनोरंजन, फूड एवं आर्टिजन मार्केट का अद्भुत समन्वय देखने को मिलेगा।

इस फेस्टिवल के दौरान फूड फेस्टिवल, लाइव म्यूजिक शो, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कॉमेडी और काव्य संध्या, खेल गतिविधियां, युवा जोन और फैमिली एंटरटेनमेंट जोन सहित कई कार्यक्रम नागरिकों और पर्यटकों के लिए खुले रहेंगे।

शहर के नागरिक और विदेशी सैलानियों के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए हेरिटेड वॉकिंग टूर्स और सिंधु भवन रोड पर वेडिंग शॉपिंग एक्सपीरियंस जोन, इस सीजन की वेडिंग शॉपिंग को प्रीमियम टच देंगे। इस फेस्टिवल में मेजर ब्रांड्स, होटल, मॉल, रिटेल, क्लॉदिंग, गिफ्ट, रेस्टोरेन्ट और अन्य क्षेत्रों से जुड़े ब्रांड भागीदार बने हैं।

फेस्टिवल को डिजिटल रूप से सुलभ बनाने के लिए एएसएफ का अधिकृत मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल लॉन्च किए गए हैं। ऐप के माध्यम से विशेष ऑफर, इंटरेक्टिव मैप, इवेंट के रीयल-टाइम अपडेट तथा एएमटीएस (सिटी बस) और बीआरटीएस में फेस्टिवल के दौरान निःशुल्क यात्रा की सुविधा वाले शॉपर पास के साथ-साथ विशेष डील और लकी ड्रॉ का अवसर मिलेगा।

इस वर्ष एएसएफ में 8000 से अधिक व्यवसायी जुड़े हैं, जिनमें रिटेल स्टोर्स, मॉल, एमएसएमई, होटल, रेस्टोरेन्ट, कारीगर और प्रीमियम ब्रांड का समावेश होता है। शहर में वोकल फॉर लोकल को प्रोत्साहन देने के लिए वस्त्रापुर में स्वदेशी मॉल, कॉटेज इंडस्ट्री प्रदर्शनी और स्थानीय कारीगरों की विशेष भागीदारी भी आकर्षण का केंद्र बनेगी।

फेस्टिवल के दौरान ग्राहकों को शहर के आउटलेट्स (दुकानों) में 15 से 35 फीसदी तक का डिस्काउंट दिया जाएगा। हंग्रिटो, वीकएंड विंडो, फन ब्लास्ट और विभिन्न सांस्कृतिक एवं मनोरंजन कार्यक्रमों के दौरान पूरे शहर में उत्सव का माहौल बन जाएगा।

अहमदाबाद शहर देश और दुनिया के आगंतुकों का इस अनोखे व्यापार, संस्कृति और मनोरंजन के भव्य उत्सव में स्वागत करने के लिए आतुर है। स्वदेशी गौरव, रिटेल इनोवेशन और आधुनिक शहरी जीवन शैली के समन्वयन के साथ एएसएफ 2025-26 अहमदाबाद को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रिटेल के नक्शे पर एक नई पहचान दिलाएगा।

फियो ने 23वें इंडिया-रूस सालाना समिट के नतीजों की प्रशंसा की; संयुक्त वक्तव्य को संतुलित द्विपक्षीय व्यापार, औद्योगिक सहयोग और निर्यात ग्रोथ के लिए एक मज़बूत प्रोत्साहन बताया

(जीएनएस)। नई दिल्ली, 5 दिसंबर, 2025: : फ़ेडरेशन ऑफ़ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइज़ेशन्स (फियो) ने 23वें इंडिया-रूस सालाना समिट के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य का स्वागत किया है और इसे दोनों देशों के बीच व्यापार आर्थिक, टेक्नोलॉजिकल और कनेक्टिविटी साझीदारी को मज़बूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है।

इन घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, फियो अध्यक्ष श्री एस सी रल्हन ने कहाः "संयुक्त वक्तव्य इंडिया-रूस व्यापार और आर्थिक सहयोग को गहरा करने के लिए एक साफ़ और बड़ा रोडमैप दिखाता है। संतुलित और स्थायी व्यापार ग्रोथ, बेहतर औद्योगिक सहयोग, लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी और नई टेक्नोलॉजी पर आधारित साझीदारी पर ज़ोर देना, दीर्घकालिक प्रतिबद्धता का एक मज़बूत संकेत देता है। निर्यातक इस स्पेशल और प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की पूरी क्षमता को प्रकट करने पर इंडिया के नए फोकस से उत्साहित हैं।"

श्री रल्हन ने कहा कि प्रोग्राम 2030 और 2030 तक दोनों देशों के बीच 100 बिलियन डॉलर के व्यापार की तरफ काम करने का पक्का इरादा एक बड़ा पड़ाव है। उन्होंने कहा, "टैरिफ और नॉन-टैरिफ रुकावटों को दूर करने, लॉजिस्टिक्स लिंक को बेहतर बनाने, पेमेंट के आसान तरीके पक्का करने और इंश्योरेंस और रीइंश्योरेंस फ्रेमवर्क को मजबूत करने की प्रतिबद्धता रूस को भारत के निर्यात को बढ़ाने के

लिए बहुत ज़रूरी होगा। ये वही दिक्कतें हैं जिनका हमारे निर्यातक सामना कर रहे हैं, और यह देखकर अच्छा लगता है कि उन्हें सबसे ऊंचे लेवल पर प्राथमिकता दी जा रही है। जैसे-जैसे व्यापार वॉल्यूम बढ़ रहा है, यह ज़रूरी है कि व्यापार बास्केट और ज़्यादा डायवर्सिफाइड और संतुलित हो, जिससे दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लिए लंबे समय तक निर्वहनीयता पक्की हो।"

फियो ने एडवांस्ड हाई-टेक्नोलॉजी सेक्टर, इंडस्ट्रियल क्लस्टर, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और जॉइंट वेंचर में गहरे सहयोग के लिए नेताओं की कोशिशों पर ज़ोर दिया। श्री रल्हन ने कहाः "समिट के नतीजों से इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मास्यूटिकल्स, एग्रो-प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, और टेक्नोलॉजी सर्विसेज़ जैसे सेक्टर में भारतीय निर्यातकों के लिए नए रास्ते खुलेंगे। मज़बूत औद्योगिक साझीदारी से न सिर्फ़ व्यापार में विविधता आएगी, बल्कि दोनों देशों के बीच लंबे समय तक सप्लाई-चेन में मज़बूती भी आएगी। इसके अलावा, रशियन मार्केट में ऑनलाइन कंज्यूमर गुड्स की बढ़ती मांग भारतीय निर्यातकों के लिए ई-कॉमर्स से चलने वाले रिटेल निर्यात -खासकर लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स, हेल्थ और वेलनेस, होम डेकोर और वैल्यू-एडेड फूड आइटम्स जैसी कैटेगरी - में बड़े अवसर देती है।"

फियो ने नेशनल करेंसी में द्विपक्षीय सेटलमेंट, पेमेंट और फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम की इंटरऑपरेबिलिटी, और डिजिटल करेंसी प्लेटफॉर्म पर कंसल्टेशन को बढ़ाने के एग्रीमेंट का भी स्वागत किया। श्री रल्हन ने कहा, "मज़बूत और अंदाज़ा लगाने लायक पेमेंट सिस्टम की तरफ़ बढ़ने से व्यापार ट्रांज़ैक्शन काफ़ी आसान हो जाएँगे और भारतीय निर्यातकों के लिए अनिश्चितताएँ कम होंगी। यह इंडिया-रूस व्यापार फ़्लो को स्थिर करने की दिशा में एक बड़ा बदलाव लाने वाला कदम है।"

फियो ने ऑयल और गैस, पेट्रोकेमिकल्स, एलएनजी / एलपीजी इंफ्रास्ट्रक्चर और न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स समेत एनर्जी में फिर से पक्के सहयोग और निवेशकों के मुद्दों को तेज़ी से हल करने की प्रतिबद्धता की तारीफ़ की। श्री रल्हन ने कहा, "स्थिर एनर्जी सहयोग भारत की औद्योगिक कॉम्पिटिटिवनेस के लिए ज़रूरी है, और इससे अप्रत्यक्ष रूप से कई तरह के निर्यातोन्मुखी क्षेत्रों को फ़ायदा होगा।"

फियो ने आईएनएसटीसी, चेन्नई-व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर जैसे ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को मज़बूत करने और नॉर्दर्न सी रूट पर सहयोग पर नेताओं के फ़ोकस की तारीफ़ की। श्री रल्हन ने कहा, "बढ़ी हुई कनेक्टिविटी से लॉजिस्टिक्स लागत कम होगी, ट्रांज़िट का अंदाज़ा बेहतर होगा और भारतीय वस्तुओं के लिए रूस और बड़े यूरेशियन रीजन में नए अवसर खुलेंगे।"

फियो ने रशियन फ़ार ईस्ट और आर्कटिक में बढ़े हुए सहयोग का भी स्वागत किया, जिसमें खेती, मिनरल, मैनपावर मोबिलिटी, फार्मास्यूटिकल्स, समुद्री ट्रांसपोर्ट और डायमंड के अवसर शामिल हैं। उन्होंने कहा, "इस क्षेत्र में भारतीय निर्यातकों और निवेशकों के लिए बहुत ज़्यादा संभावना है, जिसका अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ है। निरंतर इंस्टीट्यूशनल सहयोग से इन फ्यूचर-ओरिएंटेड ज्योग्राफ़ीज़ में भारत की आर्थिक मौजूदगी बढ़ाने में मदद मिलेगी।"

श्री रल्हन ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि संयुक्त वक्तव्य में साफ़ तौर पर एक आगे की सोच वाला और बड़ा सहयोग एजेंडा बताया गया है। उन्होंने आगे कहा, "यह निर्यातक समुदाय के लिए सही समय पर मिला प्रोत्साहन है। फियो इन प्रतिबद्धता को ठोस ट्रेड नतीजों में बदलने, ज़्यादा डायवर्सिफाइड और बैलेंस्ड ट्रेड स्ट्रक्चर को बढ़ावा देने और रशियन मार्केट में इंडिया के निर्यात परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए तैयार है – जिसमें उभरते ई-कॉमर्स रिटेल निर्यात के अवसर भी शामिल हैं।"

पश्चिम रेलवे चलायेगी साबरमती और दिल्ली के बीच स्पेशल ट्रेन

(जीएनएस)। हाल ही में इंडिगो की कई उड़ानें रद्द होने की वजह से अहमदाबाद-दिल्ली कॉरिडोर पर यात्रियों की आवाजाही पर असर पड़ा है, पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की मांग एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए ट्रेन ऑन डिमांड (TOD) साबरमती और दिल्ली जं. के बीच विशेष किराये पर चलाने का निर्णय लिया गया है। इस ट्रेन का विवरण निम्ननानुसार है:

ट्रेन संख्या 09497/09498
साबरमती-दिल्ली जं. सुपरफास्ट स्पेशल (4 फेरे)

ट्रेन संख्या 09497 साबरमती-दिल्ली स्पेशल 7 और 9 दिसंबर 2025 को साबरमती से 22.55 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 15.15 बजे दिल्ली पहुंचेगी।

इसी तरह ट्रेन संख्या 09498 दिल्ली–साबरमती स्पेशल 8 और 10 दिसंबर 2025 को दिल्ली जं. से 21.00 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 12.20 बजे साबरमती पहुंचेगी।

मार्ग में दोनों दिशाओं में यह ट्रेन महेसाणा, पालनपुर, आबूरोड, मारवाड़ जं.,अजमेर, जयपुर, अलवर, रेवाड़ी, गुडगाँव एवं दिल्ली केंट स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन में एसी 3-टियर श्रेणी के कोच रहेंगे।

यह ट्रेन कुल दूरी 925 किमी कवर करती है, जिसमें यात्रा का समय लगभग 16.20 घंटे (साबरमती-दिल्ली) और 15.20 घंटे (दिल्ली–साबरमती) है। यह व्यवस्था यात्रियों को फ्लाइट रद्द होने की स्थिति में विश्वसनीय और समयबद्ध कनेक्टिविटी प्रदान करती है और छुट्टियों के दौरान अतिरिक्त क्षमता सुनिश्चित करती है।

ट्रेन संख्या 09497 की बुकिंग 06 दिसंबर 2025 से सभी पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के ठहराव, समय और संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

6 और 9 दिसंबर को पोरबंदर-दिल्ली सराय रोहिल्ला एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग से चलेगी

(जीएनएस)। उत्तर पश्चिम रेलवे के गांधीनगर-जयपुर स्टेशन के पुनर्विकास कार्य के चलते ब्लॉक लिए जाने के कारण भावनगर मंडल से होकर जाने वाली पोरबंदर–दिल्ली सराय रोहिल्ला एक्सप्रेस ट्रेन के संचालन में अस्थायी परिवर्तन किया गया है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी के अनुसार प्रभावित ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार है:

1. ट्रेन संख्या 20937 पोरबंदर–दिल्ली सराय रोहिल्ला एक्सप्रेस दिनांक 06.12.2025 एवं 09.12.2025 को पोरबंदर से चलने वाली यह ट्रेन अपने निर्धारित मार्ग फुलेरा–जयपुर–रेवाड़ी के स्थान पर परिवर्तित मार्ग वाया फुलेरा–रींगस–रेवाड़ी संचालित होगी। इस अवधि में यह ट्रेन किशनगढ़, फुलेरा एवं जयपुर स्टेशनों पर नहीं ठहरेगी।

2. ट्रेन संख्या 20938 दिल्ली सराय रोहिल्ला–पोरबंदर एक्सप्रेस दिनांक 08.12.2025 को दिल्ली सराय रोहिल्ला से चलने वाली यह ट्रेन अपने निर्धारित मार्ग रेवाड़ी–जयपुर–फुलेरा के स्थान पर परिवर्तित मार्ग वाया रेवाड़ी–रींगस–फुलेरा संचालित होगी। इस अवधि में यह ट्रेन जयपुर, फुलेरा एवं किशनगढ़ स्टेशनों पर नहीं ठहरेगी।

रेल यात्रियों से विनम्र अनुरोध है कि वे उपरोक्त परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा की योजना बनाएं तथा ट्रेनों के परिचालन से संबंधित नवीनतम जानकारी के लिए www.enquiry.indianrail.gov.in पर अवलोकन करें, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।

आईआईटी खड़गपुर और जीएसआई का हाथ मिलाना-भारत के भू-विज्ञान अनुसंधान में नई ऊर्जा, नए रास्ते

(जीएनएस)। खड़गपुर/जयपुर। भारत के वैज्ञानिक परिदृश्य में शुक्रवार का दिन एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आया, जब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) खड़गपुर और भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण भारत (जीएसआई) ने भू-विज्ञान के उभरते क्षेत्रों में संयुक्त शोध को नई गति देने के लिए एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता जयपुर में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन "अतीत का उत्खनन, भविष्य का निर्माण : जीएसआई के 175 वर्ष" के उद्घाटन सत्र में संपन्न हुआ, जहां भारत की वैज्ञानिक विरासत और भविष्य की चुनौतियों—दोनों पर समान रूप से जोर दिया गया।

समारोह का माहौल अपने आप में ऐतिहासिक था। एक ओर 175 साल पुराने जीएसआई की विरासत का जश्न मनाया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर देश के सबसे प्रतिष्ठित प्रौद्योगिकी संस्थान में से एक आईआईटी खड़गपुर वो हाथ थाम रहा था, जिससे आने वाले दशकों में भारत के भूवैज्ञानिक अध्ययनों की दिशा बदल सकती है। मंच पर आईआईटी खड़गपुर के प्रोफेसर मनीष ए. ममतानी और जीएसआई के महानिदेशक असीत साहा के बीच समझौते का आदान-प्रदान हुआ, जबकि संस्थान के निदेशक प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती ने औपचारिक रूप से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी सहित वरिष्ठ वैज्ञानिकों और अधिकारियों की उपस्थिति ने इस साझेदारी को और अधिक वज़न दिया।

इस समझौते का दायरा बेहद विस्तृत है और इसका असर आने वाले वर्षों में देश के खनिज संसाधनों, ऊर्जा क्षमता, आपदा प्रबंधन और यहां तक कि ग्रह विज्ञान के शोध पर भी पड़ेगा। दोनों संस्थान मिलकर महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की खोज के आधुनिक तरीकों पर काम करेंगे—ऐसे खनिज जो इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरी तकनीक, सौर ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र के लिए अनिवार्य हैं। साथ ही, भू-तापीय ऊर्जा जैसे स्वच्छ और स्थायी ऊर्जा स्रोतों पर भी संयुक्त अध्ययन किया जाएगा, जो देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता में बड़ा योगदान दे सकता है। ग्रह भू-विज्ञान के क्षेत्र में यह साझेदारी अंतरिक्ष अनुसंधान को भी नई दिशा देगी। प्रारंभिक जीवन के अध्ययन से लेकर पृथ्वी के प्राचीन भू-आकृतियों और उनकी कड़ियों को समझने तक, वैज्ञानिकों को व्यापक प्लेटफॉर्म मिलेगा। आपदा जोखिम मूल्यांकन पर संयुक्त कार्य भविष्य में भूकंप, भूस्खलन, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की क्षमता को मजबूत करेगा—जो सीधे तौर पर देश के करोड़ों लोगों की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है।

व्यावहारिक स्तर पर यह सहयोग डेटा साझाकरण, फील्ड अभियानों, तकनीकी प्रशिक्षण और संयुक्त शोध परियोजनाओं के माध्यम से विकसित होगा। शोधार्थियों, युवा वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों को ऐसे अवसर मिलेंगे, जो पहले केवल अंतरराष्ट्रीय सहयोग में ही संभव थे।

इस समझौते के साथ भारत ने यह संकेत दे दिया है कि वह न केवल अतीत का उत्खनन करेगा, बल्कि भविष्य का निर्माण भी उसी वैज्ञानिक प्रतिबद्धता और दृष्टि के साथ करेगा। दोनों संस्थानों की यह साझेदारी देश की वैज्ञानिक क्षमता, संसाधन प्रबंधन की रणनीतियों और वैश्विक भू-विज्ञान समुदाय में भारत की भूमिका को एक नई ऊंचाई दे सकती है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने ऊंझा में मेनाबा रोटरी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शिलान्यास किया

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि यह हॉस्पिटल पूरे उत्तर गुजरात के लिए एक आधुनिक आरोग्य धाम बनेगा

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में गुजरात में मेडिकल सीटों में हुई बड़ी वृद्धि
- पीएम मोदी ने 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवच देकर जनकल्याण का दृष्टिकोण अपनाया है

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने शुक्रवार को ऊंझा में 10 बीघा के विशाल कैम्पस में आकार लेने वाले अत्याधुनिक मेनाबा रोटरी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शिलान्यास किया।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान सर्वांगीण विकास की मजबूत नींव रखकर जनकल्याण का दृष्टिकोण अपनाया है, इसके परिणामस्वरूप आज दूरस्थ क्षेत्रों में भी अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हुई हैं।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह हॉस्पिटल पूरे उत्तर गुजरात के लिए एक आधुनिक आरोग्य धाम बनेगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के इस यज्ञ में अपना योगदान देने वाले सभी दानदाताओं को सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र में बदलाव लाने के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा क 11 वर्षों के उनके कार्यकाल में चिकित्सा सेवा के साथ-साथ चिकित्सा शिक्षा में भी आमूल परिवर्तन आया है।

जब वे गुजरात में मुख्यमंत्री थे, तब राज्य में 1175 मेडिकल सीटें थीं, उनके दूरदर्शी नेतृत्व में सीटों की संख्या में बड़ी वृद्धि हुई है। इसके चलते अब दूरस्थ गांवों में भी डॉक्टरों की सुविधा आसानी से मिलने लगी है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने और महंगे उपचार के खर्चों को कम करने के लिए आयुष्मान योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक की मुफ्त उपचार व्यवस्था की है। राज्य सरकार ने इसमें 5 लाख रुपए और जोड़कर गुजरात की जनता को कुल 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य रक्षा कवच प्रदान किया है।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि आज राज्य की हर तहसील में डायलिसिस सेंटर और हर जिले में कीमोथेरेपी सेंटर शुरू हो गए हैं, जिसके कारण लोगों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ता। ऊर्जा एवं पेट्रोकेमिकल्स मंत्री श्री ऋषिकेश पटेल ने कहा कि डॉक्टर और कुशल मेडिकल स्टाफ स्वास्थ्य सेवा के लिए एक बुनियादी जरूरत है और प्रधानमंत्री ने इस जरूरत को पूरा करने रके लिए मेडिकल सीटों में बड़ी वृद्धि की है। उन्होंने कहा कि राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) और उप जिला अस्पताल जैसा एक मजबूत ढांचा विकसित हुआ है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह हॉस्पिटल अपनी रणनीतिक स्थिति के कारण सड़क दुर्घटना जैसी गंभीर आपदा में बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। ऊंझा में बनने वाले इस हॉस्पिटल का भवन 1 लाख वर्ग फुट क्षेत्र और 10 बीघा के विशाल कैम्पस के साथ अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा। हॉस्पिटल में ही 4 ऑपरेशन थियेटर, 200 से अधिक बेड, 20 आईसीयू बेड और 20 स्पेशलिटी क्लिनिक्स की सुविधा उपलब्ध होगी। हॉस्पिटल में जनरल मेडिसिन, न्यूरो एवं स्पाइन, ऑर्थोपेडिक, प्रसूति और स्त्री रोग, कार्डियोलॉजी, ऑन्को सर्जन और क्रिटिकल केयर जैसे सभी महत्वपूर्ण विभाग कार्यरत होंगे।

चिकित्सा आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर आईवीएफ, नवजात शिशुओं और बच्चों के लिए नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट (एनआईसीयू) और पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट (पीआईसीयू), कीमोथेरेपी सेंटर और गायनेक लेबर रूम जैसी विशेष सुविधाएं भी शामिल की गई हैं। यही नहीं, सातों दिन, चौबीसों घंटे सेवाओं के तहत फार्मेसी, लेबोरेटरी, सीटी स्कैन, डिजिटल एक्स-रे, ब्लड बैंक और आईसीयू ऑन व्हील जैसी निर्णायक सुविधाएं मरीजों की तत्काल देखभाल के लिए उपलब्ध होंगी।

सांसद श्री हरिभाई पटेल, मयंकभाई नायक और बाबूभाई देसाई ने इस अवसर पर अपने शुभकामना संदेश दिए।

शिलान्यास कार्यक्रम में प.पू. 1008 महंत श्री जयरामगिरिजी गुरुश्री बळदेवगिरिजी महाराज, विधायक सर्वश्री के.के. पटेल (ऊंझा), मुकेशभाई पटेल (मेहसाणा), सरदारभाई चौधरी (खेरालू), सुखाजी ठाकोर (बहुचराजी), राजेन्द्रभाई चावड़ा (कड़ी) और किरीटभाई पटेल (पाटण), ऊंझा नगर पालिका अध्यक्ष सुश्री जिज्ञाबेन पटेल, एपीएमसी ऊंझा के चेयरमैन श्री दिनेश पटेल, अग्रणी श्री गिरीश राजगोर, कलेक्टर श्री एस.के. प्रजापति, जिला विकास अधिकारी डॉ. हसरत जैसमीन और हॉस्पिटल के दानदाताओं सहित बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे।